**श्री सभापति:** यह तय नहीं हुआ था। ...(**व्यवधान**)...

**श्री वी. हनुमंत राव:** दो घंटे तक हम उन्हें सुनते रहे। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: He will have the right to reply.

**श्री सभापति:** आप बैठिए। बैठिए। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, I have listened with great interest to what Shri Jaswan Singhji had to say. I regard Shri Jaswant Singhji as a man of honour and a decent man, and it is precisely because I hold him in such high esteem that I requested him. You are levying serious charges against the people in the PMO. Not only in the previous PMO. In once of your television interviews, you said, 'we were snooped, we are being snooped', implying that the present PMO also has a mole. And, it is in that context, I appeal to your sense of chivalry that if you have any evidence, you should name that person, and if you do not name the person, I think, let the country draw its own conclusions. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The matter is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI JASWANT SINGH: Sir, ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: Please listen to what the Leader of the Opposition has to say. ...*(Interruptions)*...

**श्री सभापति:** बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... We are now taking the Cantonments Bill, 2003. ...*(Interruptions)*...

---

## GOVT BILLS
## THE CANTONMENTS BILL, 2003

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : Mr. Chairman, Sir, I beg to move

> "That the Bill to consolidate and amend the law relating to the administration of cantonments with a view to impart greater democratisation, improvement of their financial base to make provisions for developmental activities, proper regulation, control and management of defence lands including extension of cantonment laws to such lands situated througout the territory of India and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."...*(Interruptions)*...

Sir, I would also move the amendments. ...*(Interruptions)*... Sir, the hon. Members are aware of ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It is the Contonments Bill. He has spoken on it. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, it was decided that after the Prime Minister's observation, we will take up the normal Government business, and this Bill is the ...*(Interruptions)*... creation of Rajya Sabha, a very important Bill. Let the Bill be considered, and the hon. Members can discuss it. ...*(Interruptions)*... My respectful submission to the leaders would be, it was decided in your Chambers, Sir, that after the Leader of the Opposition completes his observations and after the hon. Prime Minister's observations, business would be taken up ...*(Interruptions)*... We need to conduct the business of the House. Is it fair that we come here everyday and waste time? I think there is no point in this ...*(Interruptions)*... Therefore, my most respectful submission would be that this is an important Bill ...*(Interruptions)*...The Bill was referred to the Parliamentary Standing Committee. The Parliamentary Standing Committee made substantial recommendations and after recommendations were made, Government considered them. The hon. Members must know ...*(Interruptions)*...my most respectful submission to you would be even in your ...*(Interruptions)*...the Bill should be passed...*(Interruptions)*... The Bill must be allowed to be passed ...*(Interruptions)*...because of the disruptions from hon. Members. Therefore, my most respectful submission is that it is a 1924 Bill; the first Cantonment Act was enacted in 1924. And today, we are living in 2006.

It is absolutely necessary that this House should give...*(Interruptions)*...Should I sit down, Sir?...*(Interruptions)*...I would like the Bill to be taken up ...*(Interruptions)*...I can wait till the commotion is cleared, but let us take up the Bill today. This is not the way to function...*(Interruptions)*...I commend that the debate be started...*(Interruptions)*...After that, I would like to respond to the debate...*(Interruptions)*...

*The question was proposed.*

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till 3.00 p.m.

The House then adjourned at
thirty-one minutes past two of the clock.

The House reassembled at three of the clock,
Mr. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

**श्रीमती सुषमा स्वराज** (मध्य प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति जी। उपसभापति जी, मैं रक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए "The Cantonments Bill, 2006" पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

उपसभापति जी, मेरा जन्म एक छावनी क्षेत्र में हुआ। अम्बाला कैंट में मैं जन्मी, वहीं पली, पढ़ी, बड़ी हुई। उसके बाद मेरा राजनैतिक सफर भी अम्बाला कैंट में ही शुरू हुआ। मैंने दो बार अम्बाला कैंटोनमेंट का एमएलए के तौर पर हरियाणा विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद जब मैं दक्षिण दिल्ली से सांसद चुनी गई, तो दिल्ली कैंटोनमेंट मेरे संसदीय क्षेत्र में आता था। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि रक्षा मंत्री जी को यह बता दूं कि मैंने एक निवासिनी के तौर पर भी छावनी की समस्याओं को भोगा है और एक जनप्रतिनिधि के नाते भी छावनी की समस्याओं को जाना और समझा है। इसलिए मैं जो कुछ भी इस बिल के बारे में यहां कह रही हूं, वह कहीं से पढ़ा या सीखा हुआ नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर कह रही हूं।

रक्षा मंत्री जी, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगी कि यह बिल बहुत बड़ा है। इसमें 365 धाराएं हैं, 5 अनुसूचियां हैं, यह बिल 140 पृष्ठों में चलता है। इस बिल में आपने अपनी ओर से 60 संशोधन प्रस्तुत किए हैं आपको मेरा सुझाव है कि जब भी कभी इतनी बड़ी संख्या में संशोधन प्रस्तुत किया जाना हो, तो पुराने बिल को विदड्रॉ करके, वापस लेकर एक नया बिल नए रूप में देना हमेशा अच्छा रहता है। क्योंकि यह बिल जब आपने पिछली बार दिया, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, तब तो मालूम नहीं था कि सरकार की ओर से क्या संशोधन आने वाले हैं और अब एकदम 60 संशोधनों का पुलिन्दा आ गया। आप जानते हैं कि संशोधन अलग से नहीं पढ़े जा सकते। संशोधन पढ़ने के लिए मूल बिल को साथ रखना पड़ता है। क्योंकि संशोधन में तो लिखा ही यही होता है कि पृष्ठ इतने पर धारा इतनी, पंक्ति इतनी, उसमें फलां को फलां पढ़ा जाए, उसका लोप कर दिया जाए, उसको संशाधित कर दिया जाए। बार-बार पन्ने पलटते-पलटते 60 संशोधनों के बारे में, कई बार तो खीझ होने लगती है और बहुत असुविधा होती है। सांसदों को पढ़ने में जो असुविधा हुई, मुझे जो असुविधा हुई, वह तो हुई, लेकिन रक्षा मंत्री जी, असुविधा आपको भी होने वाली है, जिस समय आप ये संशोधन मूव करने के लिए खड़े होंगे। हमारे यहां यह प्रथा नहीं है कि आप 60 के 60 संशोधन एक साथ मूव कह दें। आप देखिएगा, मैं भी यहीं हूं और आप भी यहीं हैं। आप बहुत उत्साह से शुरु करेंगे।

**श्री उपसभापति:** मुझे भी असुविधा होगी।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** मैं उस पर आ रही हूं। उसमें आप शुरु इससे करेंगे...

SHRI PRANAB MUKERJEE: You are absolutely correct.

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** आप पहले कहेंगे, "I move my amendment number so and so. I move my amendment number so and so." 10 तक यह सिलसिला चलेगा, उसके बाद आप कहेंगे, "I move my amendment." 30 तक आते-आते आप कहेंगे, "I move, I move." सर, आपको करीब 100 बार उठक-बैठक करनी पड़ेगी। मेरी असुविधा के बाद आपको असुविधा भोगनी पड़ेगी। तीसरी असुविधा पीठासीन अधिकारी को भोगनी पड़ेगी। 60 संशोधन पारित करवाने में अगर एक-एक मिनट भी हम लगाएं ayes, noes, put up करना। इस सारे में इस बिल को पारित करने में एक घंटा लगेगा और उतनी ही इन सांसदों को पड़ेगी, जो ayes, noes, ayes, noes कहते रहेंगे। इस सारे से बचा जा सकता था, अगर आप इस बिल को विदड्रा कर लेते। उन 60 संशोधनों का इसमें समावेश करते हुए एक नया बिल रख देते, तो पहली बार में ही हम जो बिल पढ़ते, उसे नए रूप में पढ़ते और आप भी यहां पर इस सारी की सारी असुविधा से बच जाते। वैसे मैंने भी आपकी थोड़ी-सी असुविधा बढ़ा दी है, पर मेरे पास चारा नहीं था। मैंने संशोधन तो बहुत बनाए थे, मैंने 25 संशोधन बनाए थे। मगर आपकी इस असुविधा को देखते हुए मैंने इसे 11 कर दिया है। मुझे इसे 11 इसलिए करना पड़ा, क्योंकि एक तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं कि मैं बिल में संशोधन लाऊं। मैं तो केवल संशोधन के रूप में ही संशोधन ला सकती हूं। लेकिन दूसरी बात यह भी थी कि मुझे संशोधन ऐसे लगे, जिन्हें शायद आप स्वीकार कर लें। मैं जानती हूं, दलीय प्रजातंत्र में संख्या बल पर संशोधन आते हैं। अगर संख्या बल पर इस हाउस में वोटिंग हुई तो निश्चित तौर पर मेरे संशोधन गिरेंगे, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन के बारे में जब मैं बोलूंगी तो शायद उन्हें स्वयं आप का मन चाहेगा और हो सकता है आप उन को स्वीकार कर लें। उस समय यदि आप मुझे कहते कि आप का सुझाव तो अच्छा है, लेकिन यदि आप अमेंडमेंट देतीं तो मैं स्वीकार करता। इसलिए आप को यह हैंडल न मिल जाय, यह बहाना न मिल जाय, इसके लिए मैंने आज संशोधन प्रस्तुत किए हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस में 11 संशोधन प्रस्तुत कर रही हूं। यह सुझाव देने के बाद अब मुझे लगता है कि आन ने पहले ही कह दिया कि I am correct क्योंकि आप इस तरह की असुविधाओं से बहुत बार गुजरे होंगे, as a Finance Minister जब आप फाइनेंस बिल पास कराते थे, लेकिन कैंटोनमेंट बिल पर आप को यह असुविधा सहनी पड़ेगी, इस की आप ने कल्पना नहीं की थी। पहला केन्टोनमेंट एक्ट 1924 में बना था। आज 82 वर्षों के बाद हम इस कैंटोनमेंट एक्ट को संशोधित कर रहे हैं। अब 82 वर्षों में तो दुनिया बदल गयी है, एक बेचारे कैंटोनमेंट की क्या बिसात है। पहले जो जनसंख्या थी वह कई-कई गुना हो गयी और जब जनसंख्या कई-कई गुना हो

गयी और साधन उतने ही रहे तो समस्याऐं कितनी गुना हो गयीं, उनकी तकलीफ कितने गुना हो गयीं? इसीलिए आप ने जब कैंटोनमेंटों का वर्गीकरण किया तो बजाय 3 से 4 भागों में किया। उपसभापति जी, 1924 के एक्ट में कैंटोनमेंट को तीन श्रेणियों में बांटा जाता था और आप हैरान होंगे सबसे बड़ा कैंटोनमेंट 10 हजार से ऊपर वाली जनसंख्या का बनता था। लेकिन आज रक्षा मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, उस में सब से बड़ा कैंटोनमेंट 50 हजार से ऊपर की जनसंख्या का रखा है और 10 हजार से ऊपर व 50 हजार से नीचे के कैंटोनमेंट को श्रेणी दो में रखा गया है, ढाई हजार से ऊपर और 10 हजार से नीचे की जनसंख्या को श्रेणी तीन में रखा गया है व ढाई हजार तक के कैंटोनमेंट को श्रेणी चार में रखा गया है। यह आपने नई श्रेणी बनायी है, लेकिन जब मैं इस बिल के उद्देश्य व कारणों का विवरण पढ़ती हूं तो उसमें 5 उद्देश्य दिखाई देते हैं जिसमें सब से पहला वृहत्तर लोकतंत्रीकरण है जिसके आप ने greater democratisation कहा है। अब वृहत्तर लोकतंत्रीकरण के नाम पर आप यह बिल लाए हैं, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे कि यह बिल अभी तक जो लोकतंत्र चल रहा था, उस लोकतंत्र को भी कम कर रहा है और कहीं-कहीं तो उसे नकार रहा है।

मैं एक बात आप को यहां हाथ जोड़कर निवेदन कर दूं कि जवाब देते समय यह मत कहिए कि यह आप के समय का बिल है। यह 2003 में बना था और इस के नीचे जॉर्ज फर्नांडिस का नाम लिखा है क्योंकि ''मीठा-मीठा गप्प और कड़ुआ-कड़ुआ थू'' नहीं चल सकता, या तो आप हमारे किए हुए तमाम कामों को आंकिए, लेकिन जहां आप को सूट करता है, वहां आप बदल देते है। आपने ''पोटा'' निरस्त कर दिया, लेकिन कैंटोनमेंट बिल पर आप यह कह दें कि यह तुम्हारे समय का बिल है। हां, हमारे समय बिल ड्राफ्ट जरूर हुआ था, लेकिन जब बिल ड्राफ्ट होता है तो मंत्री उसे नहीं देखता, अधिकारी उस को ड्राफ्ट करते हैं। उस के बाद जब स्टेंडिग कमेटी को जाता है और स्टेंडिग कमेटी की अनुशंसाएं आती हैं। उस समय जरूर उसे मंत्री को देखना चाहिए क्योंकि उस समय बिल में जनता की भावना समाविष्ट हो चुकी होती है। जब हम स्टेंडिंग कमेटी में बैठते हैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बैठते हैं, दलीय सीमाओं को लांघ जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी अनुशंसाएं कमेटी में आती हैं। आप ने 60 संशोधन दिए हैं, मुझे दुख के साथा कहना पड़ता है कि कमेटी ने जितनी अनुशंसाएं लोगों को राहत देने वाली की थीं, जितनी अनुशंसाएं इस बिल को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए की थीं, उनमें से आपने एक भी स्वीकार नहीं की है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि 60 संशोधन आप की तरफ से आए, लेकिन एक भी संशोधन जो वाकयी इस को लोकतंत्रीकरण की तरफ बढ़ाता, इस का लोकतंत्रीय स्वरूप और ज्यादा बड़ा करता, उसे आपने स्वीकार नहीं किया। मैं उदाहरण देना चाहूंगी, उपसभापति जी, मैं छोटी बात से शुरू करती हूं। कैंटोनमेंट बोर्ड का एक अधिकारी होता है सी॰ई॰ओ॰ उस को अभी तक 1924 एक्ट के तहत कैंटोनमेंट एक्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता

था, आज इस 2006 वाला बिल उसे चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर बता रहा है। आप कहेंगे क्या फर्क हो गया, जरा सा भाषा का हेरफेर है? नहीं, उपसभापति जी, यहा भाषा का हेरफेर नहीं है, यह भावों का हेरफेर है, यह अधिकारों का हेरफेर है। जब आप किसी को कैंटोनमेंट का चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, तो आप के मन में एक शक्ल बनती है कि वह कैंटोनमेंट का एक अधिकारी होगा, कार्यकारी अधिकारी होगा जो एक्जीक्यूटिव फंक्शस करता होगा। जब आप उसे किसी को इंट्रोडयूस कराते हैं, और कहते हैं, he is a Chief Executive Officer, तो आप के मन में एक सूरत बनती है, अच्छा यह कैंटोनमेंट का सर्वे-सर्वा होगा यह cantonment का मुखिया-जैसा होगा और यह सच है। आपने केवल भाषा ही नहीं बदली, उसको केवल Chief executive officer का दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि आपने उसके अधिकार बढ़ाकर उसको वाकई सर्वेसर्वा बना दिया। मुझे दुख इस बात का है कि जो बात मैं कह रही हूँ, वह स्टैंडिंग कमेटी ने भी कही थी। स्टैंडिंग कमेटी ने तो यहाँ तक कहा था कि उसे बोर्ड का मैम्बर भी नहीं रहना चाहिए, केवल एक्जिक्यूटिव रहना चाहिए। अगर आपको संशोधन स्वीकार करना चाहिए था, तो सबसे पहले यह स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया। मैं आपको Recommendation पढ़कर बताती हूं। मैं यह स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ।...(व्यवधान)... मैं यह पेज 13 पर recommendation 3.10 and 3.11 पढ़ रही हूँ: "The Committee, after carefully examining the suggestions, given by various organisations/associations and individuals are also of the view that the CEO should not be made the member of the Board." यह है उसकी रिकमेंडेशंस। 3.11 में है कि "The Committee feels that the CEO should act only as an executive to carry out legislative instructions of the Board and should be accountable to the Board. कमेटी आपको कहती है कि आप CEO को मैम्बर मत बनाइए। उसको केवल एक्जिक्यूटिव फंक्शंस करने दीजिए और उसके साथ-साथ उसे बोर्ड के प्रति भी उत्तरदायी बनाइए। लेकिन आपने बोर्ड को क्या बनाया? मैं आपको धारा-दर-धारा, clause-after-clause पढ़कर सुनाना चाहूँगी कि कहाँ-कहाँ जो अधिकार पहले वहाँ के निर्वाचित सदस्यों के पास थे, आज आपने वह लेकर CEO को दे दिए। रक्षा मंत्री जी, आपको मालूम है कि 1924 के एक्ट में, टैक्स का जो एसेसमेंट होता है, उस एसेसमेंट पर जब आपत्तियाँ सुनी जाती हैं, तो उसका अधिकार एक एसेसमेंट कमेटी को था, जो निर्वाचित सदस्यों से बनती थी। अब यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि जब टैक्स का एसेसमेंट होता है, उससे बहुत से लोग त्रस्त होते हैं। वे अपनी आपत्तियां सुनाना चाहते हैं। जब पब्लिक के लोग बैठते हैं, तो वे उसको बहुत संवेदनशीलता से सुनते हैं। इन्होंने उस एसेसमेंट कमेटी की बात हटाकर एसेसमेंट करने का वह अधिकार

आज CEO को दे दिया है। अब एसेसमेंट कमेटी उसको नहीं करेगी, आपत्तियां सुनने की जो बात थी, अब वह आपत्तियां नहीं सुनेगी, बल्कि वह CEO सुनेगा।

दूसरी बात, एसेसमेंट लिस्ट का जो authentication होता था, वह कमेटी का मैम्बर करता था। अब इन्होंने कह दिया कि CEO प्रेसिडेंट की अप्रूवल से यह करेगा। प्रेसिडेंट भी यहां निर्वाचित सदस्य नहीं है, उसको मैं बाद में बताउंगी। वह भी स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर था। CEO प्रेसिडेंट की अप्रूवल से लिस्ट को authenticate करेगा, जो पहले एसेसमेंट कमेटी का मैम्बर करता था। इस तरह वह भी आपने हटा दिया। एसेसमेंट लिस्ट का संशोधन, एमेंडमेंट पूरे-का-पूरा बोर्ड करता था। फुल बोर्ड बैठता था, जिसमें सारे निर्वाचित सदस्य बैठते थे। वह आपने हटाकर CEO को दे दिया। क्योंकि यह इतना बड़ा बिल है, इसलिए मैं सारी धाराओं को एक साथ नहीं बता सकती, लेकिन मैंने आपको ये तीन उदाहरण दिए हैं कि आज का आपका यह बिल CEO को सर्वेसर्वा बना रहा है और एसेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी जैसी चीज़ को भी आम लोगों से, निर्वाचित सदस्यों से हटाकर CEO को दे रहा है। इस पर भी कमेटी का रिकमेंडेशन है। कमेटी का रिकमेंडेशन वही है, तो मैं कह रही हूं। 5.5, पेज 35 में है कि - "The Committee further feels that the objection received to evaluation or asssment should be enquired into or investigated by a committee consisting of both nominated and elected members of the board or civil area committee instead of conferring this power on CEO," लेकिन, यह आपने नहीं माना।

अब मैं आपको वृहत्तर लोकतंत्र का दूसरा पहलू बताती हूं। रक्षा मंत्री जी जो बिल लाए हैं, उसकी धारा 12, उपधारा 3 और छ, वह 6 नहीं है बल्कि अंग्रेजी का G है, उसमें आपने निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर, जो पहले सात थी, अब आठ कर दी है। आप उसको डेमोक्रेटाइजेशन, ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन बता रहे हैं कि आपने एक निर्वाचित सदस्य बढ़ा दिया। इसी तरह category 2 में धारा 12 की उप धारा 4 और छ, यानी G, में आपने सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 कर दिया है। इस तरह एक-एक सदस्य बढ़ाया है और इसको ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन कहा जा रहा है कि हमने निर्वाचित सदस्यों की संख्या एक बढ़ा दी है। लेकिन उपसभापति जी, ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन के मायने हैं कि nominated और *ex-officio,* यानी मनोनीत और पदेन सदस्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम-से-कम एक ज्यादा हो, तो हम उसको डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन यह कुल संख्या कितनी बन रही है? एक्स-ओफिसियो, नोमिनेटेड भी 8 और इलेक्टेड भी 8, कुल मिलाकर 16, एक भी संख्या ऊपर नहीं। इसी तरह कैटेगरी दो में 7 और 7, कुल 14, एक भी

संख्या ऊपर नहीं। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहती हूं, जो सुविधा की दृष्टि से कहना चाहती हूं कि जहां कहीं भी, रक्षा मंत्री जी, जिस किसी भी संस्था में निर्णय वोटिंग से होने का प्रावधान हो, वहां नंबर ओड होना चाहिए, इवेन नहीं। ओड नंबर होता है, तो एक ही बार में फैसला हो जाता है, जैसे यदि 15 सदस्य हो तो 8 और 7 वोट पड़ेगें ज्यादा से ज्यादा। अब यहां हर निर्णय में 8 और 8 होने लगें, सपोज निर्वाचित सदस्य सारे एक तरफ हो जाएं और नोमिनेटेड, एक्स-ओफिसियों एक तरफ हो जाएं, तो आपके लिए तो हर दिन झगड़ा। फिर आप इसे कैसे करेंगे? क्या आप वीटो पावर देंगे प्रेसीडेंट को या ड्रा ऑफ लोट्स करेंगे, लॉटरी से निकालेंगे? अगर आप ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन चाहते थे, तो निर्णय निर्वाचित सदस्यों की संख्या एक बढ़ाकर के किए जाने चाहिए थे, आपने इवेन नंबर लाकर के कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यह बहुत छोटे-छोटे संशोधन मैंने दिए हैं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो, कोई प्रिस्टेज का सवाल नहीं है, सरकार के साथ हम इसमें हैं, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कह रही हूं, जो मेरे दल को फायदा देगी, इसलिए इसको आप कर सकते हैं और जहां मैंने यह कहा है कि 8 सदस्यों की जगह 9 कर दीजिए और 7 से 8 कर दीजिए, तो संख्या 16 की जगह 17 हो जाएगी, अनइवेन यानी ओड हो जाएगी और जहां यह संख्या 14 है वहां पर 15 हो जाएगी, अनइवेन यानी ओड हो जाएगी। इससे आपका ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन का उद्देश्य, बृहत्तर लोकतंत्र का आपका उद्देश्य पूरा हो सकेगा क्योंकि निर्वाचित सदस्यों की संख्या, चाहे एक ही ज्यादा हो, मगर नोमिनेटेड और एक्स-ओफिसियो से ज्यादा होगी।

महोदय, इसी श्रृखंला में मैं यह कहना चाहती हूं कि धारा-19 की उपधारा-1 में आपने कहा है कि स्टेशन कमांडिंग ऑफीसर प्रेसीडेंट होगा, अध्यक्ष होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हम इसको म्युनिसपैलिटी का दर्जा देंगे, कैंटोनमेंट को आपने डीम्ड म्युनिसपैलिटी यानी नगरपालिका माना है। किसी भी नगरपालिका में क्या प्रेसीडेंट कोई अधिकारी होता है? हमने 73वां और 74वां संशोधन पारित किया। जितनी हमारी निर्वाचित बॉडीज हैं, सब में चुना हुआ सदस्य अध्यक्ष होता है, कुछ जगहों पर तो डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान है, कुछ जगह मेयर डायरेक्ट चुना जाता है, कुछ जगह मेयर जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे चुना जाता है, लेकिन कहीं भी अधिकारी अध्यक्ष नहीं होता है। जिला-परिषद जो हैं, उस जिला-परिषद का अध्यक्ष भी अधिकारी नहीं होता, जिला-परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है, नगर-पंचायत के अध्यक्ष चुने जाते हैं, इवेन गांव के सरपंच चुने जाते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कैंटोनमेंट इलेक्टेड बॉडी है, ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन भी है और आप दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि डीम्ड म्युनिसपेलिटी भी है, लेकिन धारा-19 की उपधारा-1 में आपने कहा है कि स्टेशन कमांडिंग ऑफीसर प्रेसीडेंट होगा। जब स्टेशन कमांडिंग ऑफीसर प्रेसीडेंट होगा, तो डेमोक्रेसी कैसे होगी? इसलिए मेरा यह भी सुझाव है कि आप चाहें तो मेयर की तरह डायरेक्ट चुनाव करा सकते हैं, अगर नहीं तो जो मैंने एक संशोधन

दिया है कि अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से होगा, मान लीजिए। आप इतना तो करें कि जो 8 लोग चुनकर आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा, अगर आप मान लें 9 लोग, तो उन 9 लोगों में से आप निर्वाचित सदस्यों से अध्यक्ष बनाएंगे, तो वाकई लगेगा कि आप ग्रेटर डेमाक्रेटाइजेशन की तरफ बढ़े हैं, वरना यह बात केवल इस किताब में लिखी हुई पढ़ लेंगे कि यह बृहतर लोकतंत्रीकरण के लिए बिल लाया गया है, जब कि वास्तव में वह लोकतंत्र इसमें कहीं दिखता नहीं है। इसका तीसरा पहलू बृहत्तर लोकतंत्र के विरोध में जाता है, वह यह कि आपने इसमें टैक्स कितना लगेगा, क्या लगेगा, इसका भी फैसला स्वयं कर दिया है एक्ट के माध्यम से। आपने यह धारा 68 में कह दिया है कि जो कर लगेगा, यह कर 10 परसेंट से कम नहीं होगा और 30 परसेंट से ज्यादा नहीं होगा। कौन सी म्यूनिसपल कमेटी एक्ट से तय करते है कि आप कितना टैक्स लगाएंगे और किस चीज पर टैक्स लगाएंगे? इस बिल की धारा 66और 67 में यहां आपने कहा है कि यह-यह कर लगेंगे, इस पर आपकी स्टेंडिंग कमेटी ने कहा है कि आप यह डबल टैक्सेमन करने जा रहे हैं। मैं आपको स्टेंडिंग कमेटी की रिकमेंडशन पढ़कर सुनाती हूं। स्टेंडिंग कमेटी की रिकमंडेशन है - पेज 34, पैराग्राफ 5(2) में – "The Committee feel that the mater of levying property tax and other taxes in the cantonment area needs a flexible regime. If these conditions are laid down in the Act, it could become rigid. The Committee feel that the existing provision of the cantonment Act, 1924 should be retained in the present Bill. The Committee desire that all efforts should be made to ensure that civil residents of the cantonment areas are not subjected to double taxation." धारा 66 में इन्होंने स्वयं तय कर दिया है कि कौन-कौन सी जगह पर प्रापर्टी टैक्स लैवी किया जा रहा है। इसी तरह से धारा 67 में तय कर दिया है कि फीस कहां-कहां ली जाएगी। 67 पर भी स्टेंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है:-

"The Committee note that under sub-clause(e) of this clause, there is a provision to charge lincence fee on entry of vehicles. All types of vehicles of the residents of cantonment are taxed by the Regional Transport Officer who recovers tax as well as licencee fee for vehicles. The Committee feel that imposing taxes by the Cantonment Board may lead to double taxation. Therefore, the Committee desired that vehicles of the residents of the cantonment areas should not be subject to this fee as they may have to fequently travel outside the cantonment area."

और जैसा मैंने कहा कि मैं अम्बाला कैंट में रहती हूं, मैंने इनको स्वयं भोगा है। अम्बाला कैन्टोन्मेंट में ऐसा एरिया है जो बिल्कुल साथ लगता है और सिविल एरिया म्युनिसिपल कमेटी का बन जाता है। एक समय था जब यह सारे का सारा कैन्टोन्मेंट एरिया था, लेकिन हम लोग धन्यवाद

देते है हैं जब चौधरी बंसी लाल रक्षा मंत्री बने तो अम्बाला कैंट से यह ज्ञापन आया, यह मांग पत्र आया कि इस एरिया को एकसीड कर दें, कुछ सिविल एरिया हमें दे दें, जहां हमें बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। तो काफी बड़ा एरिया अम्बाला कैन्टोन्मेंट से निकाला गया और सिविल एरिया बना। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरा एक घर कैन्टोन्मेंट एरिया में था और एक घर सिविल एरिया में था। हम लोग रहते सिविल एरिया में थे, लेकिन हमारा एक बंगला था - बंगला नं॰ 75, माल रोड, कैन्टोन्मेंट एरिया में। अब अगर वहां से हम अपने 75 नम्बर बंगले में जाएं, सुबह मैं पढ़ने के लिए जाया करती थी, अगर हम वहां जाएं और शाम को अपने घर आएं, तो क्योंकि व्हीकल एक बार कैन्टोन्मेंट एरिया में जा रहा है और एक बार म्युनिसिपल एरिया में आ रहा है, तो आप भी हमसे फी लेंगे और यह भी हमसे फी लेंगे। तो इतना बेतुका यह कर है, जिसको खुद कमेटी ने कहा है कि यह डबल टेक्सेशन है। और ये चीजें एक्ट में लिखी जाती हैं क्या? मैं बार-बार जो इनसे कह रही हूं कि 66 और 67 में, आपने प्रापर्टी टैक्स की बात की, 67 में आपने लेवी ऑफ फीस की बात की और यह भी बताया कि फीस किन-किन चीजों पर लगेगी, पर 68 में तो आपने यह भी बता दिया कि 10 परसैंट से कम मत लगाना और 30 परसैंट से ज्यादा मत लगाना। उपसभापति जी, अगर किसी एक इलेक्टिड बॉडी को ग्रेटर डिमोक्रेटाइजेशन के नाम पर लाया गया और उस बाडी को इतना भी अधिकार नहीं है कि वह अपने टैक्स की सीमा तय कर सके, वह भी एक्ट बताएगा तो हंसी आती है। यहां बी॰जे॰पी॰ के लोग बैठे हैं, उनको ध्यान होगा कि कर्नाटक में 'उडुपी' की जो म्युनिसिपल कमेटी है, परम्परागत ढंग से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हैं आपने कभी सुना होगा वहां कि 'उडुपी' की नगर पालिका ने कभी कोई टैक्स नहीं लगाया, और हमेशा प्राफिट में रही! यह उदाहरण है, पूरे देश में यह अनुकरणीय उदाहरण है 'उडुपी' नगर पालिका के लोगों ने कभी कोई टैक्स नहीं लगाया, तब भी वह प्राफिट में है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि कम से कम आप इतना तो छोड़िए। इसलिए उसका भी मैंने संशोधन दिया, जहां मैंने कहा है कि ये कर लगेंगे, लेकिन उसके आगे कहा है कि जहां 10 परसैंट से 30 परसैंट है, उसका लोप कर दिया जाए, मैंने बोला है कि उसको आप हटा दें। क्योंकि अगर आप यहां से तय करेंगे तो फिर वहां बैठकर लोग तय कैसे कर सकेंगे। किसी कैन्टोन्मेंट में किसी तरह की चीजें हैं, किसी कन्टोन्मेंट में कैसे सरकमस्टांसिज हैं, जैसे पूरा देश यूनिफार्म नहीं है, बहुत चीजों में विविधताएं हैं ऐसी कैन्टोन्मेंट की भी विविधताएं हैं, लेकिन आप यहां तय कर रहे हैं 10 परसैंअ से कम और 30 परसैंट से ज्यादा नहीं लगाएंगे, इस पर भी मैंने एक संशोधन दिया है।

इसी तरह से दो छोटी-छोटी चीजें आप इस बिल में लाए हैं कि वोटर लिस्ट हर वर्ष बनेगी। सर, कहीं हुआ है ऐसा आज तक? वोटर लिस्ट चुनावी वर्ष में बने, यह तो समझ में आता है, पर वोटर लिस्ट हर वर्ष बनेगी! कितना पैसा खर्च होता है वोटर लिस्ट बनाने में, कितना काम बढ़ता है। हम वोटर लिस्ट को हर वर्ष बनाकर क्यों यह ख्वामख्वाह काम बढ़ाना चाहते हैं? आप कहिए कि वोटर लिस्ट चुनावी वर्ष में बनेगी।

इसी तरह से आपने कहा है कि असैसमेंट हर तीन साल में होगी। बगल में नगर पालिका में असैसमेंट 5 साल में हो रही है। आप तो जानते हैं, सर, जब असैसमेंट होती है तो टैक्स बढ़ता ही बढ़ता है। तो जो बराबर की नगर पालिका है, उसमें तो असैसमेंट हो रही है 5 साल में और आप इसमें कह रहे हैं 3 साल में होगी। आपकी स्टेंडिंग कमेटी ने कहा है कि 5 साल की होनी चाहिए, उन्होंने बोला है। मैं पढ़ रही हूं पेज 36, पैरा 5.8:-

"In view of the suggestions received from the non-official witnesses, the Committee recommends that new assessment list should be prepared every five years instead of three years, as provided in the clause." इसका मतलब यह है कि यह सुझाव कमेटी ने वैसे ही नहीं दे दिया। सर, जब यह बिल उनको रैफर हुआ तो स्टैंडिंग कमेटी के लोगों ने पब्लिक ओपीनियन के लिए, कहते हैं न कि to elicit public opinion, यह बिल लोगों को दिया। जगह-जगह से ऐसोसिएशन्स, इंडीवीजुअल्स और ऑर्गनाइजेशन्स आई, उनके सामने उन्होंने ज्ञापन दिए। अम्बाला कैंट बंगलों ओनर्स ऐसोसिएशन के लोगों ने भी ज्ञापन दिया और जब मैं उधर उस ज्ञापन को और इधर स्टैंडिंग कमेटी की रिपार्ट्स को देख रही थी तो मैं हैरान हो रही थी। रक्षा मंत्री जी, मैं आपको यह बताना चाहती हूं, उस ज्ञापन में दिए गए बिन्दुओं में से 90% बिन्दुओं के साथ स्टैंडिंग कमेटी ने सहमति जताई है और यह सिफारिशें की हैं, जो जनता चाहती है। वह अकेले अम्बाला कैंट बंगलो ओनर्स ऐसोसिएशन से नहीं आया हुआ है, सारे कैन्टोनमेंट की लगभग एक-सी समस्याएं हैं, सब लोगों ने आ कर कहा होगा। इस तरह उन्होंने 90% बिन्दु माने, लेकिन मुझे दु:ख से कहना पड़ता है कि आपने एक भी नहीं माना। जो बिल उनके पास गया, वह बिल मूल रूप का ही है। आपने 60 संशोधन दिए हैं, उन साठों संशोधनों को पढ़ने में मुझे चार घंटे का समय लगा, लेकिन मेरा जरा सा भी समाधान नहीं हुआ। हमारे यहां से आए हुए एसोसिएशन के बिन्दुओं को कमेटी ने इतना अच्छा समझा कि 90% बिन्दुओं के ऊपर उन्होंने सहमति जताई है, हमारे पक्ष में रिकमेंडेशन किया है, जिन्होंने ज्ञापन दिए, उन ज्ञापनों के पक्ष में किया है, लेकिन आपने साठ संशाधनों के बावजूद एक भी संशोधन स्वीकार नहीं किया। आप मेरी वेदना समझ सकते हैं? मैंने बिल को पढ़ने के बाद इतना समय उस पर लगाया, लेकिन एक जगह भी मुझे राहत की सांस दिखाई नहीं दी कि आपने स्टैंडिंग कमेटी का कोई रिकमेंडेशन माना हो।

आपने इसका एक उद्देश्य बताया है कि मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस लैंड और लैंड पॉलिसी। यह जो लैंड पॉलिसी की बात है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आप जानते हैं कि डिफेंस की टोटल लैंड 17,31,000 एकड़ है, जिसमें से 2,00,000 एकड़ कैन्टोनमेंट्स के पास है और 15,31,000 एकड़ डिफेंस के पास है। सीएजी तक की रिपोर्ट्स भी हैं कि यह मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है और सर, मैं आपको कहना चाहती हूं कि कभी किसी कैन्टोनमेंट में जाकर वहां के रहने वाले लोगों की दुर्दशा देखिए। बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जो जमीन मिलनी

चाहिए, वह जमीन भी कैंटोनमेंट नहीं देता है। जैसा कि मैंनें कहा कि जनसंख्या कितनी गुनी हो चुकी है, उस कई गुना हो चुकी जनसंख्या का आकलन करते हुए आपने अपना कैंटेगराइजेशन बढ़ा दिया और 'श्रेणी एक' का कैन्टोनमेंट आपने 50,000 से ऊपर कर दिया जो 10,000 से ऊपर था।

सर, वहां पर टॉयलेट्स नहीं हैं, सैनिटेशन नहीं हैं, पार्क्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, डिस्पेंसरीज नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं। वहां पर रहते तो लोग ही हैं न, रहते तो इन्सान ही हैं न, क्या ये सारी चीजें उन्हें नहीं चाहिए? लेकिन वह मिलिटरी की लैंड है, उसे आप इतना सा भी छू नहीं सकते। प्राइवेट लैंड नहीं है, जिसे आप खरीद कर बना लें। बाकी जगह पर तो प्राइवेट अस्पताल बन जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स बन जाते हैं, कहीं-कहीं पर लोग नगरपालिका से जमीने ले लेते हैं, वहां ये चीजें बना देते हैं। चूंकि वह डिफेंस की लैंड है, आप एक इंच जमीन भी नहीं ले सकते, लेकिन आपकी इस लैंड पॉलिसी के कारण वहां पर लोग इस तरह से रह रहे हैं कि लगता है जैसे नारकीय जीवन बिता रहे हों।

सर, मैं जिस बंगले की बात कर रही हूं, मैं बहुत बार अपने पिता जी से कहती थी कि बाऊ जी, हम वहीं जाकर रहेंगे क्योंकि वहां रहने के लिए मेरा मन करता है, लेकिन चूंकि वहां पर आप कुछ बदल ही नहीं सकते, घर पुराने पुराने बने हुए हैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं वहां पर साईकिल लेकर पढ़ने चली जाती थी कि चलो वहां पर पढ़ कर आऊंगी। वहां पर आऊट हाउसिज थे और उन आऊट हाउसिज में जो लोग रहते थे, उनकी दुर्दशा देख कर मुझे रोना आता था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। आप उसकी छत नहीं बदल सकते, आप उसकी दीवार नहीं बदल सकते, आप उसका फर्श नहीं बदल सकते आप अन्दर भी काम नहीं करवा सकते। मतलब यह है कि लोग वहां पर नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यह कैसी लैंड पॉलिसी है? आपने लैंड लेकर बेची है, वहां इन्सान रहते हैं और उन इन्सानों की जनसंख्या दस, बीस या पचास गुनी हो गई है। उन्हें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, डिस्पेंसरी चाहिए उन्हें टॉयलेट्स चाहिए, लेकिन कैन्टोनमेंट में लैंड पॉलिसी ऐसी बनी हुई है कि आप उनके लिए कुछ नहीं दे सकते। कृपा करके आप अपनी लैंड पॉलिसी को बदलिए। मैनेजमेंट ऑफ लैंड्स के अंदर जो लैंड डिफेंस के पास है, आप उसे रखिए, आप उस पूरे को मैनेज करिए या फिर उसमें से सिविल एरिया काटिए, लेकिन आपने जो कैन्टोनमेंट में जमीने दी हैं उनके साथ ऐसा न कीजिए।

अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूं, शायद आपको मालूम होगा अन्यथा आप लिख लीजिए, अम्बाला में एक माली परेड नाम की जगह है। डेढ़ सौ साल से वहां पर वह माली रहते हैं उनके पास कोई बड़े खेत नहीं हैं, बीघों में जमीनें हैं और वे केवल सब्जी बोते हैं। मुझे वैसे ही वह सब्जी के खेत अच्छे लगते थे और वैसे भी वह मेरी वह मेरी कांस्टीटयूएंसी का हिस्सा था इसलिए मैं वहां पर जाकर बैठ जाती थी। वहां पर गोभी, मूली उगे हुए हैं, वे केवल सब्जी की

खेती करते थे। उनके पास बहुत छोटे-छोटे खेत हैं, वे केवल एक-एक या दो-दो बीघे जमीन के मालिक हैं और डेढ़ सौ साल से वहां हैं। हर चौथे महीने उनके सिर पर तलवार लटका दी जाती है कि तुम्हें उजाड़ रहे हैं। बीसियों बार तो मैंने जाकर के वे नोटिसेज रुकवाए। हर रक्षा मंत्री के सामने गुहार की, लेकिन चूंकि आज बिल के ऊपर बोलने का मौका मिल रहा है, रक्षा मंत्री जी, मैं पूरी वेदना के साथ जो भी वजन मेरा है उसके साथ, राजनीतिक वजन की बात कर रही हूं, मैं गुहार करना चाहती हूं कि इस मसले का आप हल निकलवा दीजिए, डेढ़ सौ साल से वे माली वहां बैठे हैं, जहां माली परेड की जगह कही जाती है, बहुत थोड़ी सी जगह है। यह तय हो गया था कि हरियाणा सरकार उसके बदले में उतनी जमीन उन्हें देगी और यह जमीन आप उनको एलॉट कर देंगे। लेकिन आज तक वह हुआ नहीं है और हरियाणा में अब सरकार आप ही की है। अगर आपको उसमें कोई कमीबेशी हो तो आप कर लीजिए, जितनी जमीन आपको लेनी है लीजिए। पर, मैं कहना चाहती हूं कि लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत जमीन है। क्यों लालची हो रहे हैं, क्यों लोभी हो रहे हैं। जिनके पास कम हो वह तो कहे कि डेढ़ सौ एकड़ के बदले में डेढ़ सौ एकड़ दो तब हम देंगे। आपके पास तो लाखों एकड़ जमीन है, कैन्टोनमेंट्स में आप दो लाख एकड़ के मालिक हैं। कैंटोंमेंट बोर्ड के अलावा 15 लाख 31 हजार एकड़ के मालिक हैं आप डिफेंस लैंड के, आपके लिए डेढ़ सौ एकड़ क्या मायने रखता है। लेकिन अगर उस डेढ़ सौ एकड़ को आप वहां दे देंगे तो वहां घर बस जाएंगे, हजारो घर बस जाएंगे और दूआएं देंगे लोग आपको। आपकी एक लैंड पॉलिसी के कारण वे माली परेड के लोग हर दिन बेघर होने का डर लेकर के जी रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस माली परेड का मसला सुलझा दीजिए। इसी तरह से बंगलोज में दो तरह की जमीन है, ओल्ड ग्रांट की जमीन है और लीज की जमीन है। अय लोग कहते हैं कि कानून के मुताबिक ओल्ड ग्रांट की जमीन पर आपका कोई हक नहीं है। लेकिन ओल्ड ग्रांट की जमीन के ऊपर भी आप अपना हक जमाए बैठे हैं। लोग इतनी सी चीज इधर से उधर नहीं कर सकते और हर बार आकर रोते हैं लेकिन हम अपने आपको असहाय पाते हैं, क्योंकि मिलिट्री का मामला है, बाकी कोई हो तो हम कर भी लें। इसीलिए जो मैनें प्रारम्भ में भी कहा था कि अगर निर्वाचित सदस्य कैंटोंमेंट बोर्ड में ज्यादा होंगे तो वे यह फैसले संवेदनशीलता से ले सकेंगे, चाहे वह टैक्स के एसेसमेंट का फैसला हो, चाहे वह ओल्ड ग्रांट का मसला हो, चाहे वह लीज होल्ड जमीन का मसला हो, चाहे वे इस तरह के मसले हों। अगर आप अध्यक्ष निर्वाचित बना देंगे, तो कम से कम वे लोग बैठ करके इनके फैसले संवेदनशीलता से कर सकेंगे जो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपने तो जैसा मैनें कहा कि अभी तक जो निर्वाचित सदस्य किया करते थे, आप तो वे अधिकार भी ले रहे हैं और वे अधिकार भी सी॰ई॰ओ॰ को दे रहे हैं। तो आज के बाद यह बिल पारित हो जाने के बाद तो कैंटोंमेंट बोर्ड स्टेशन कमांडिंग आफिसर और सी॰ई॰ओ॰ के द्वारा चलाया जाएगा और बाकी तो निर्वाचित सदस्य ठीक हैं, एक उनको तमगा जरूर मिल जाएगा कि वे एक बोर्ड के सदस्य चुनकर गए हैं, लेकिन जाकर बैठेंगे और चलेगी अफसरों की और

अल्टीमेटली जो वे चाहेंगे, वह होगा। आप मानिए तथा जो संवेदनशीलता एक इलेक्टेड मेंबर में होती है, जनप्रतिनिधि में होती है, वह जगह-जगह जाता है, बैठता है, वह अधिकारी में नहीं होती। यह हमसे ज्यादा कौन जानेगा, आपसे ज्यादा कौन जानेगा। इसीलिए मैं मंत्री जी के आगे गुहार कर रही हूं, वरना बीसियों बार तो वहां के अफसरों से बात हो चुकी है और आज यह मौका मिला इस अवसर का लाभ उठा करके, क्योंकि प्रासंगिक हैं यह चीजें। मैं आपके सामने कहना चाह रहीं हूं कि रक्षा मंत्री जी, केवल इन मसलों का हल नहीं करिएं बल्कि यह जो स्टैंडिग कमेटी की सिफारिशें हैं, आपको कुछ नहीं करना, स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिशात हैं, उनके आधार पर आप संशोधन ले आइए। अभी यह बिल इस रूप में पारित कराना चाहते हैं करा लीजिए, इस स्टेंडिंग कमेंटी की सिफारिशों को मुझे लगता है कि आपने देखा नहीं। और जैसे-जैसे अधिकारियों ने आगे बिल दे दिया उस तरह से आप बिल ले आएं स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को पढ़िय तो। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब विखे पाटिल थे, जिनको आपने देखा कि वे स्वंय कितने सादे, कितने भोले, कितना लोगों को जानने वाले वह व्यक्ति हैं, आप ही के दल में। लेकिन उनकी अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी ने यह सिफारिशे दी हैं, ये अनुशंसाएं दी हैं, अगर आपने इन सिफारिशों को पढ़ लिया होता और अध्ययन करने के बाद एनेलाइज कर लिया होता तो मेरा मन कहता है कि आप निश्चित तौर पर इसमें से बहुत से संशोधन स्वीकार करके लाते। लेकिन शायद व्यस्तता के कारण आप इसको देख नहीं पाए। मेरी आपसे गुहार है कि जो संशोधन आज मैं लाई हूं, वे सारे के सारे स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर आधारित हैं, 19ए और 68 को छोड़कर जो वह आपकी स्टैंडिंग कमेटी में नही है लेकिन मुझे यह लगता है कि उसके ऊपर उनका कमेंट जरूर था। लेकिन बाकी सारे के सारे संशोधन स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही मैंने बनाए हैं, उनको आज स्वीकार कर लीजिए। लेकिन बाकी जो कमेटी की सिफारिशें हैं, उनको भी लेकर के आप नया बिल लाइए। आखिरी बात, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि 1999 से लेकर कैंटोंमेंट बोर्ड के चुनाव नही हुए। वह आखिरी चुनाव था उसके बाद कैंटोमेंट बोर्ड वैरी कर दिए गए और वैरी कर जाने के बाद सात साल हो गए, चुनाव नहीं हुए। सिकन्दराबाद में एक पिटीशन डाली हुई है, उस पिटीशन पर फैसला पक्ष में हुआ है तथा 8 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं। वे पुराने एक्ट के तहत ही हो रहे हैं मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि बिल पारित हो जाने के बाद, आप यह भी आश्वासन दे दीजिए कि इस बिल के पारित होने के तुरन्त बाद आप चुनाव करायेंगे, ताकि सात वर्ष से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया Cantonment बोर्ड्स में रूकी हुई है, वह प्रक्रिया वापस शुरू हो जाए, दोबारा से चुने हुए लोग आ जाएं, लेकिन चुने हुए लोग ऐसे ही नहीं आएं, हां, एक बात और रह गई है, जिसे मैं आपसे कह देनी चाहती हूं। रक्षा मंत्री जी, आपने एम॰पी॰ और एमएलऐज को इसमें मेम्बर बनाया है। विधायक और सांसद को आपने एक्स ऑफिसियों मेम्बर इसमें बनाया है, लेकिन उनको राइट टू वोट नहीं दिया है, उनको वोट का अधिकार नहीं दिया है। आज जब डीम्ड म्युनिसिपलिटीज़ कहते हैं, तो आप देखिए कि संविधान

की धारा 243PE इसमें यह है कि जो एमएलए और एम०पी० वहां सदस्य होंगे, उनको राइट टू वोट दिया जा सकता है और बहुतों ने दिया। जब मैं दिल्ली से एम०पी० थी तो म्युनिसिपल कारपोरेशन की मेम्बर भी थी, हमें राइट टू वोट था, पंजाब में राइट टू वोट है, चंडीगढ़ में राइट टू वोट है, तो नगरपालिका में जहां सांसदों को, विधायकों को मेम्बर बनाया जाता है, वह दर्शनी दीवे बनाने के लिए नहीं बनाया जाता है कि वे वहां पर जाकर शोभा बढ़ा दें, बैठ जाएं, बल्कि इसलिए बनाया जाता है कि वह निर्णय प्रक्रिया में भागीदार हों। श्रीमती अम्बिका जी, यहा पर बैठी हैं, वह यहां दिल्ली से राज्य सभा की एम०पी० थीं, वह जरूर दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन की उस समय मेम्बर रही होंगी, Yes, a Member of Parliament from Delhi, राइट टू वोट के साथ। श्री जनार्दन जी हैं, तो मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी कि जब आपने एमएलए और एम०पी० को वहां पर एक्स आफिसियों मेम्बर बनाया है, तो उनको राइट टू वोट तो दीजिए। वह भी एक संशोधन मैंने दिया है, जिसमें मैंने कहा है कि उनको मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये तमाम चीजें, जो बातें आपके सामने कही हैं, मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि मैं केवल अपने मन की वेदना, अपने अनुभव, अपनी समझ और जो मैंने स्वयं भोगा है, उसके आधार पर मैंने ये बातें रखी हैं। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री जी, मेरी इस वेदना को समझेंगे और जो मेरे संशोधन हैं, उन संशोधनों को भी स्वीकार कर लेंगे और बाद में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नये संशोधन लाकर इस बिल को ज्यादा लोकतांत्रिक बनायेंगे, तब ते यह उद्देश्य सार्थक हो सकेगा, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी, जो इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण में लिखा है, वरना तो एक बिल और हम पारित कर देंगे और मैं आपसे कह दूं कि अगर यह बिल इसी रूप में पारित हुआ तो 1924 के बिल से ज्यादा undemocratic Bill कहा जायेगा, ज्यादा retrograde Bill कहा जायेगा, ज्यादा regressive Bill कहा जायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल** (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): उपसभापति महोदय, मैंने बड़े ध्यान से सुषमा जी का भाषण सुना। यह सही भी है, जैसा कि उन्होंने बताया कि Cantonment में उनका जन्म हुआ, तो वह आज दिल से बोल रही थीं, लेकिन जब दिल्ली के मसले पर बोलीं तब शायद दिल से नहीं बोलीं। उनके आज उद्गार सुनने वाले थे, उस दिन के उद्गार सुनने वाले नहीं थे। जो तेजी आपने आज दिखाई, वह तेजी आपने उस दिन नहीं दिखाई और मुझे खुशी है कि आज आप बहुत अच्छा बोलीं, जो मुद्दे जरूरी थे, वे भी अपने रखे..।

**श्री उपसभापति:** वह बोल रहे हैं दिल्ली के बारे में कुछ नहीं बोला।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सर, दिल्ली वाले में तो मैं सेकेंड स्पीकर थी। उस पर जेटली जी बोले थे, मुझे तो दो मिनट ही बोलने के लिए मिले थे और उस समय की वेदना तो शायद आज से ज्यादा थी। आप देखो तो सही।

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** आज वेदना ज्यादा थी।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** अपनी-अपनी समझ की बात है।

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** उस दिन बहुत कम थी। मुझे खुशी है कि मंत्री जी आप इस बिल को लाए और इस बिल की बहुत सख्त जरूरत थी। आपकी तकरीबन 62 छावनियां पूरे हिन्दुस्तान में हैं और ये एक टापू की तरह से अलग-अलग जगह पर हैं। जैसे आप दिल्ली का Cantonment एरिया ले लें, पहले जब कभी भी बना होगा, यह छावनी के नाम से जाना जाता है। मैं तो पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ हूं। उस समय कहते थे कि हम छावनी जा रहे हैं, तो यह जो एरियाज़ हैं, ये सब अब शहर के बीच में आ गये हैं और ये शहर के हिस्से हैं। आज जो यह बिल लाये हैं, इसमें ज्यादातर सिविक एमिनिटीज़ के बारे में कहा गया है। यह जो छोटे-छोटे म्युनिसिपल टाइप बोर्ड्स बनेंगे, जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के दुख-सुख का ध्यान रखेंगे या उनके लिए काम करेंगे, उसी में से वे लोग चुने जायेंगे, जो उस बोर्ड के मेम्बर बनेंगे। अच्छा तो यह होता कि आप इसमें बहुत सारे एरियाज़ को कारपोरेशन के जिम्मे करते, ताकि इससे डुप्लीकेसी नहीं होती। दिल्ली सरकार भी यही काम कर रही है और दूसरे स्टेट्स में जहां-जहां ये हैं, वहीं काम करेंगी। जैसे-बिजली है, पानी है, टैक्स है, शिक्षा है, ये सारी चीजें बजाय Cantonment के जो सिविक एरियाज़ हैं और जो आपके मिलिट्री एरियाज़ हैं, उनमें अगर कोई डिविजन करके करते, तो शायद यह डुप्लीकेसी नहीं होती। लेकिन फिर भी जो बिल आप लाए हैं, उस बिल से कैंटोनमेंट एरिया में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, उनको अपनी बात उस बोर्ड में रखने का दोबारा से मौका मिलेगा। जो कई साल से वहां चुनाव नहीं हुए और जिस तरह से वे काम करते थे, इफेक्टिवली और अधिक काम वे कर सकेंगे। इसके अलावा उनका वहां की लोकल बॉडीज़ के साथ बराबर संबंध बना रहेगा। मुझे बहुत खुशी है, मैंने तो दिल्ली में देखा था कि जो हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के मैंबर्स थे, वहां बराबर चुनाव होते थे और कांग्रेस के जो मेंबर जीतते थे, वे बहुत अच्छा काम करते थे-ज्यादातर उसमें कांग्रेस के ही मेंबर थे-वे लोगों के लिए चीखते थे, चिल्लाते थे, काम करते थें यह एक ऐसी बॉडी है, जहां लोग बैठकर अपना फैसला खुद कर सकते हैं लेकिन इस बिल में जहां अच्छाई है, वहां कुछ परेशानियां भी हैं। उन परेशानियों को वहां बैठकर वे दूर नहीं कर पाएं । उसके लिए आपको उनको और ताकत देनी पड़ेगी। जिस तरह सुषमा जी ने भी एक दो ाइंट्स कहे। जैसे लोगों के पास रेंटिड एरिया है। जब कैंटोनमेंट बने हैं, पचास-पचास, साठ-[illegible] से पुराने रेट के ऊपर जो उनके पास जगह है, जिनकी वे मरम्मत नहीं कर सकते, उसमें वे रह रहे हैं-पूरे का पूरा परिवार रह रहा है, उसमें वे कोई तबदीली नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर वे चाहते हैं कि जेनेरेशन बदलती है और अगर किसी के फादर नहीं रहे तो वह क्या करें? वहां की एजेंसी यह कहती है कि आप इस मकान को खाली करें, इस जगह को खाली छोड़कर चले जाएं। लेकिन रहने वाले वहां रहते हैं, इससे मुकदमेबाजी बढ़ रही है। उनके

बेटे वहां रहते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो रेंटिड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में कोई फैसला करें। मुझे नहीं लगता है कि इस बिल के अंदर कहीं आपने उसके बारे में एक लफ्ज भी कहा है। इससे जो लिटीगेशन है, वह भी कम होगा और वहां के रहने वालों को राहत मिलेगी। दूसरा, वहां पर बहुत सारी लीज़ होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। उनकी भी वही समस्या है। जब सारी दिल्ली में आपने लीज़ होल्ड प्रॉपर्टीज़ को फ्री होल्ड करने के लिए छूट दी है और यह कहा है कि आप एक स्पैसिफिक पैसा जमा कर दें और उसके साथ वे उसे फ्री होल्ड कर देंगे, तब यह छूट वहां पर भी होनी चाहिए ताकि जिस समस्या से वे जूझ रहे हैं, जो दिक्कत उन्हें महसूस हो रही है, उनकी वह दिक्कत दूर हो जाए। तीसरा, इसमें सिविल एरिया का है। कई बार जो उनका सिविल एरिया है, उसके अंदर लोगों को दिक्कत होती है, बोर्ड उनकी दिक्कतों को दूर नहीं कर पाता। कई बार डीमार्केशन ने होने की वजह से वे यह कह देते हैं कि हमारा एरिया नहीं है। आपके यहां जाते हैं तो आप कह देते हैं कि हमारा एरिया नहीं है। इससे उनको परेशानी होती है। सबसे ज्यादा परेशानी बिजली और पानी की होती है। कई केसिज़ ऐसे भी आए हैं कि जो टेक्स आप लगाते हैं-जो प्रॉपर्टीज़ आपके अंडर नहीं भी आतीं, उनको भी आपके यहां से पहले नोटिसेज़ जाते रहे हैं। इस प्रकार मुझे समझ में नहीं आता कि इसका हल कैसे होगा? जो वहां चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो वहां चुनाव होंगे, जो लोग चुनकर आएंगे, वे उसको दूर कर पाएंगे या आप कोई ऐसी ताकत देंगे? कोई ऐसी डिटेल होनी चाहिए जिससे उनकी वह परेशानी दूर हो सके। इसके बाद बिल में आपने कहा है-मैं सुषमा जी से सहमत हूं कि जो आपने मैंबर्स की तादाद रखी है, वह आज की तारीख में बहुत कम है । हालांकि कापोरेशन के मुकाबले या छोटी कमेटियों के मुकाबले यह कम है कि दस हजार के ऊपर तकरीबन एक मैंबर आएगा या सात हजार या आठ हजार के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर इससे ज्यादा तादाद आप बढ़ाते तो अधिक लोगों का रूझान होता, और ज्यादा काम वे कर पाते, लोगों की जो शिकायतें हैं, उन्हें सुनने के लिए ज्यादा लोग हो जाते और बोर्ड की मीटिंगों में वे उनके लिए लड़ सकते थे। इसके बाद आपने इसमें बूचड़खाने के लिए कहा। आपके जो मैंबर बनकर आएंगे, जो मैंबर्स वहां पर काम करेंगे, उन मैंबर्स को आप क्या एमिनिटीज देने वाले हैं? पहले तो उनके पास कोई साधन नहीं थे, आप टेलीफोन तक नहीं देते थे, टेलीफोन का पैसा भी उनका अपना खर्च होता था सेवा भाव है, सारी चीज़ है लेकिन अगर कुछ एमिनिटीज आप मैंबर्स को दें तो और अच्छा काम वे कर पाएंगे- ये देनी चाहिए। इसमें आपने आपने बुचड़खाने का जिक्र किया है। मुझे नहीं लगता कि उस छोटे से एरिये में-दिल्ली की बात मैं कर सकता हूं, दूसरी जगहों का मुझे मालूम नहीं- एक छोटा सा एरिया कैंटोंमेंट का होता है, उसमें बूचड़खाने की क्या जरूरत है। एक अलग slaughter house उस जगह बनाएंगे, हालांकि अब दिल्ली में environment के तौर पर कोर्ट ने भी कहा और जो प्रेजेंट बूचड़खाना पिछले साठ-सत्तर साल से था, उसको हटाकर हम नोएडा ले गए हैं, दूसरी जगह ले गये हैं, गाजीपुर ले गए हैं। मैं चाहता हूं कि यह क्लॉज अगर न हो तो ज्यादा अच्छा है। वरना एन्वायरन्मेंट की प्रोब्लम आएगी और एक छोटे से एरिया में, छोटी जगह के लिए बूचड़खाने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं नहीं समझता हूं

कि यह होना चाहिए। यदि हो सके तो आप बिल के बाद कोई ऐसी क्लॉज उनको बनाकर दें, ताकि वहां पर यह बूचड़खाना न खुले। इसके खुलने से वहां परेशानी होगी। दूसरा, आपका एरिया एयरपोर्ट के पास भी है, अगर आप वहां पर बूचड़खाना बनाएंगे तो आपको एयरपोर्ट वाले, एयर फोर्स वाले और एयर लाइन्स वाले भी कहेंगे कि यह वहां नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने इसमें एक burial ground और बर्निंग ग्राउंड के लिए इसमें लिखा है। सर, ये दिल्ली में कई जगह बने हुए हैं। छोटी तादाद के लिए अलग से बनाना कोई जरूरी नहीं है। मैं नहीं समझता कि वहां आपको कोई ऐसा ग्राउंड बनाना चाहिए। वहां एक असेम्बली का मैम्बर है, लेकिन सैन्ट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, बिलों पावर्टी लाइन के लिए भी हैं, वे कैसे लागू होंगी? क्या आपकी सिविक बॉडी उनको एडोप्ट करेगी? जिसमें से स्लम एरियाज एम्प्लूवमेंट ऑफ एन्वायरन्मेंट प्रोग्राम है, नेशनल सोशल सिक्यूरिटी स्कीम है, SCDC (POP) for scavengers है, नेशल स्लम एरियाज डेवल्पमेंट प्रोग्राम्स है, अन्नपूर्णा फॉर BPL है, Girl's betterment scheme - Rs. 500/- each on two girls birth पर हैं, इसी तरह से providing urban Structure in rural areas है, Jawahar National Urban Restructuring Mission है, इसी तरह State Urban Agenda for Rajasthan हैं, *Bharat Nirman* Programme इस तरह के कई प्रोग्राम हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपका बोर्ड ये प्रोग्राम्स एडोप्ट करके लागू करेगा या जो हमारी एसेम्बली है, उसके द्वारा लागू होगा? इसके बाद कुछ और स्कीम्स हैं, जैसे out of turn electricity Agri-Connection to BPL's (State)' जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसिज हैं, वहां उनको कौन लागू करेगा? क्या उनका स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी या आपके बोर्ड लागू करेंगे? मैं आशा करता हूं कि जो सवाल मैंने रखे हैं, आप उनका उत्तर देंगे, लेकिन अच्छा है यह बिल देर से आया, लेकिन आया और इससे हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को ताकत मिलेगी। अभी श्रीमती सुषमा जी ने कहा है कि वहां पर सात-सात मैम्बर्स होंगे, चौदह मैम्बर्स होंगे, वोटिंग नहीं होगी। दिल्ली एसेम्बली में भी 70 मैम्बर्स हैं। इन बातों का तो ज्यादा मतलब नहीं होता है, कारपोरेशन में 140 सीटें हैं, वहां भी वोटिंग होती है। वैसे odd और even नम्बर से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन, मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जो मैम्बर्स की तादाद है, उसे बढ़ा देंगे, तो इससे फायदा होगा। धन्यवाद।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, this Bill was placed before the Standing Committee, and it was discussed there. It should be considered in the context of the modern municipal management, and the modern thinking how to run the local bodies. Even that movement started here in our country, and a lot of changes took place. Sir, it has been mentioned in the aims and objectives of the Bill

that the administration in the cantonment requires greater democratisation.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.]

Sir, we all know that greater democratisation of a local body means that it should be given more power, and, at the same time, it should be more answerable to the people. That should be the basic idea. More power means, the legal power, the financial power, at the same time, they should be answerable to the people. Honble Minister knows, in many of the municipal corporations or the municipal administrations in the country, even before the Constitutional Amendment was promulgated, the Act was amended by the State Assemblies where the public representatives came at the helm of affairs. Now the Municipal Commissioner or the Chief Executive Officer, has to go to the Mayor for getting his CCR approved. The Mayor was to sign the CCR report. That was the change in many State Act. In West Bengal we have the Public Accounts Committee there. Many of the municipal administrations, even in Kolkata, Pranabda knows it very well, they have the Municipal Accounts Committee. The Chairman is from the Opposition. So, the thinking is being changed like anything. There should be more democratisation and more power to the people's representatives.

Sir, here, it has been very rightly pointed out. One Member raised the point in the Standing Committee, and I have gone through it, that the number of the public representatives should be increased. But, here in this Bill there are four categories. In the first category, one member is from the officer commanding the station as an *ex officio* member, or as the Central Government so directs. Then there is another member, the District Magistrate or the Executive Magistrate, the Chief Executive Officer. And, again, there is health Officer as a member, Chief Engineer as a member, and there are three military officers nominated by the officer commanding the station and 8 members elected under this Bill. This way, it cannot be said that we are giving more power to the people's representatives, nor can we say that we are doing more democratisation. I could not understand, when the Chief Executive Officer is there, why again there is Health Officer? Why again Executive Engineer and three military officers? So, my earnest request to the Minister is, as in all the three other categories of the Cantonment, the number of public

representatives should be more as compared to the total number. Only equal number of public representatives are there. So, this is my first observation so far as the constitution of the Cantonment Board is concerned.

Sir, if I turn page 11, clause 18(1), "Resignation", it is written, "Any elected member of a Board who wishes to resign his office may give his resignation in writing to the President"; President is not an elected member but the Vice-President is an elected member; "and who shall forward it for orders to the Central Government under intimation to the General Officer Commanding-in-Chief of the Cantonment." That is the provision there. But, in the case of the Vice-President, it is said, "in every Board, there shall be a Vice-President elected by the elected members only from amongst them in accordance with such procedure as the Central Government may by rule prescribe. The Vice-President may resign his office by notice in writing to the President and on the resignation being accepted by the Board, the office shall become vacant."

My point is, the Vice-President is an elected representative, who will act under the President, who is not an elected representative. Then, why an elected representative, who wants to resign from his office, not place his resignation to the Board? They will take a decision. That has been done in the case of the Vice-President, if he resigns, then it will go to the Board. Then, why not the same in the case of other elected representatives? That is another point I want to put it here. It is not good that the Vice-President, being a public representative, an elected person, to act under the President, who is not an elected representative. It is not democratisation as has been advocated, or wanted by the Standing Committee. Then I would like to refer to clause 29(e) on page 14 regarding qualification for being a member of the Board. I could not follow it. It is written that an officer or employee, permanent or temporary, of a Board or of any other local authority cannot contest any election. Definitely he should be a local resident. But an employee permanent or temporary or of any other local authorities, actually, this is not fair. Why should they be debarred from standing in the election?

In clause 34 on page 18 it has been written under removal of members that no member shall be removed from a Board under sub-section (1) of sub-section (2) of this section unless he has been given a

reasonable opportunity of showing cause against his removal. My point is he should be heard. In the Bill only by showing cause one can be removed. He should be given proper opportunity to be heard. This provision should be there in this clause relating to removal of members.

Then if we take clause 49(2) one page 21 here, it is written under joint action with other local authority that if any dispute takes place or if any difference of opinion arises between any Board or other local authority acting together under this section, the decision thereon of the Central Government or an officer by the Central Government in this behalf shall be final. Suppose an elected local authority comprising of Elected members, in that the decision of the Central Government or an officer appointed by it shall be final. What is the role of the concerned State Government? Why should they not be there? That is another point that is missing here that I wanted to mention.

Then clause 60 (1) is regarding supersession of Board. As Pranabbabu would agree with me, it is very hurting for me at least because many elected members of the Municipal Boards, I am one of them, were superseded without showing any reason. I have that pain with me. Anyway, here under supersession of Board it is written that it can be superseded for such a period as may be specified in the order. When there will be election it should be specified and it should be mentioned that supersession would be for such period. What will be the time, it should be mentioned here. No board should be superseded unless they are given opportunity to be heard against supersession. So, supersession period should be mentioned that this is the period. It should be specified very categorically. They should be heard. The Board should be heard. The period should be mentioned here categorically. Yes, you can supersede a body if there are any offenders but the supersession period should be mentioned.

Then last but one point is regarding clause 109 regarding special provision relating to taxation, under payment to be made to a Board a service charges by the Central Government or the State Government. I would like to point out here that for many years I was in the local bodies. Many of the Ministers are here and it was a constant demand of all the local bodies even in the All India Council of Mayors where I was the Senior Vice-Chairman and we raised that point that why should not the local authorities have the power to get property tax from the Central

4.00 P.M.

Government assets? I remember categorically, when I was the Mayor at that time, hon. V.P. Singh was the Prime Minister, I got a reply from the Central Government that the Government of India is moving in the same direction. As suggested by the Municipal body, a body was formed. One of our officers was there. Out Minister knows very well about Kolkata. About 1/3rd of the properties of Kolkata belong to the Central Government. But the municipal corporations are not getting any property taxes. So, it was decided that our Constitution will be amended. So, whenever I get any opportunity I raise this point, as a man from the local body for many years there. Here also, I put the same questions. Why not the local bodies get the property tax of the Government Assets? One point has been raised here that why the MLAs and MPs haven't the right to vote. I do not prescribe that because MPs and MLAs and representatives of local bodies are moving separately with their aims and objectives. They may be included, but the MPs and MLAs should not have the right to vote in the local bodies. That should be managed by the local public representatives there. They should be made more answerable to the people. That is my suggestion. The last point is this: The Cantonments Bill is aimed at consolidating Cantonment Board mechanism and democratisation. In the Cantonment areas, many civilian institutions also operate and the Cantonment Boards and the Defence Ministry as an ultimate authority should remain sensitive to the needs of the civilian institutions and their activities. The Cantonment Boards are already playing that role, but still there are some grey areas. I cite an example. The Steel Authority of India Limited is having a stockyard at Pune which falls under the Dehu Road Cantonment area. Owing to high octroi duty charged by the Cantonment Board at two and a half per cent the consumption of steel materials from the said stock year in the Cantonment area got discontinued as price became uncompetitive. In response to the representation made by the local traders and SAIL Employees Union, led by Mr. Jibon Roy, our former Member of Parliament in the Rajya Sabha, Cantonment Board recommended a lower octroi duty on steel material at 0.2 per cent. But this happened three years ago. But still now, the lower octroi duty is not implemented, as the recommendation has not yet been approved by the Defence Ministry. The matter was brought to the notice of the Defence Minister about a year back by Mr. Jibon Roy, the former MP, but still the decision is hanging there. I would also like to request the Minister to look into this matter.

With these few words, with an observation and a very serious observation on points, relating to the democratisation of the authority and about superseeding of the Board, I conclude my views. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Thank you, Mr. Chatterjee. Now, Shrimati S.G. Indira. She is not there. Shri Mangani Lal Mandal. He is not there. Shrimati N.P. Durga.

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Sir, thank you for having given me an opportunity to speak on this Bill. I welcome the Bill moved by Shri Pranab Mukherjee. The aim of the Bill is laudable. But, still there are some loopholes which need to be plugged. Otherwise, the situation of having democracy in the British-conceived cantonments, which also house civilians, would remain illusory, since there would not be any democratisation in real sense as has been envisaged in the Bill. As we know, there are 62 Cantonments in the country administered by the Cantonments Act. And, these Cantonments cover only 2 lakh2 of the total 17.31 lakh hectares of Defence land. At the same time, there are 600 military stations, which neither come under the Cantonments nor under municipalities. Military stations differ from Cantonments in the sense that there is no resident civilian population at military stations, despite having a large resident population of armed forces personnel, their families and some commercial establishments. I would like to know as to what are problems that the Ministry have to bring them along with Cantonments under this legislation because, with the insertion of Part IX-A *vide* 73rd Amendment to the Constitution, these military stations could either be brought under cantonments or the respective State Governments so that they can take benefits of district planning, grants-in-aid, etc. I would also like to know whether the Government is planning to extend Seventh Schedule of the Constitution to military stations. Or, why cannot you insert a new Clause in the Bill to define military stations as a new category of cantonments? Otherwise, they are under executive instructions which do not have any statutory value.

The next point I wish to make is with regard to Clause 12 of the Bill. Under this Clause, you are constituting the Cantonment Boards and, of course, you have different categories of cantonments i.e., Category I to IV. But, if you look at the composition, it tilts towards bureaucratic character with military domination. The aim of the Bill is to have greater

democracy and autonomy in the Cantonments. How can they exercise autonomy or how can there be democracy when you have only eight elected members, for example in Category-I, and 8 nominated members? When there is a tie, the ex-officio Presidents casts his vote and the elected representatives have little say since their decision is over-ruled by the ex-officio President by casting his vote. Moreover, in the Bill, there is no provision to remove the President as has been done in the case of Vice-President. I wish to know from the Minister the reasons behind this discrimination. Then, Sir, cantonments are also represented by local MLA/MP. But, you have not made them members of the Board to cast their vote. After all, they represent cantonment and are also worried about its development. So, is it not prudent to make them members of the Board? I wish to know the reasons behind deleting them from the development process of the cantonment.

Now, Sir, I come to Clause 56 of the Bill which gives drastic over-riding powers to the President of the Board to suspend any resolution passed by the Board and refer the same to the General Officer Commanding-in-Chief. The role of the GOC-in-Chief is irrelevant in the context of the local-self-Government. This gives a clear indication that the cantonments are administered by military--not as has been envisaged in the Bill--by undemocratic means! So, the cantonments are *de jure* autonomous local self-governments but in real terms the local self-government is illusory.

As we all know, the moment you say cantonment, we will know that it is full of disputes. The people in cantonments are facing a lot of problems with regard to execution of Conveyance Deed, etc. It is because the documents start from 'Old Grant' to Lease to Licence. Due to this, a lot of legal complications arise. And, as a result, the civilians are not able to execute the Conveyance Deed. Since I come from Hyderabad, I am personally aware of this. Sir, Secunderabad is the largest cantonment in the country. One of the major demands of the people in this Cantonment is to merge this with the local municipality for better services like sanitation, drinking water, electricity, etc. Shri Chandrababu Naidu when he was the Chief Minister wrote a letter to the Ministry of Defence to merge all civil areas of Secunderabad Cantonment with the Municipal Corporation of Hyderabad as it was agreed by the Government to merge some of the other Cantonments with local municipalities. But, the

Government decided that because of the security reasons this should not be merged with the MCH. If you merge this with MCH, the army can have a greater control on those pockets where you have stationed your troops. Sir, the other problem in this Cantonment is, the slum colonies in this Cantonment are denied from getting DFID funds. There are seven wards in this Cantonment. But, there is no reservation for women on the Board. The people are demanding for scrapping Octroi and Toll Tax. Hence, I implore upon the hon. Minister to kindly merge this Cantonment with the MCH.

Sir, Clause 27 deals with elections and preparation of electoral rolls of cantonments. Here, the Clause is silent that within a prescribed period the electoral rolls would be prepared. Hence, I request the hon. Minister to make it mandatory for revising the electoral rolls in every two years or whatever is appropriate.

Then, though it is not directly related to the Bill, I wish to take the liberty and would like to know from the hon. Minister as to what has happened to Nakra Committee's recommendation for dividing military stations into three categories--first is purely military area, the second one is a buffer zone for purely commercial and service activity and thirdly a civil area.

So, with these words, I conclude my views on the Bill and request the Minister to respond to those when he replies to the debate. Thank you.

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कैंटोनमेंट बिल के बारे में सुषमा जी ने विस्तार से प्रकाश डाला है और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने जो सुझाव दिए, उनमें से बहुत से सुझावों से मैं सहमत हूँ लेकिन एक बात उन्होंने यह कही, कि यह बात मत कहिएगा कि बिल हमारे समय में आया था। बिल का निर्माण तो पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस आलोक में कहना चाहूंगा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि यह बिल सदन में आने से पहले मंत्री जी इसे दो स्तर पर देखते हैं, एक तो अनुमोदन करने के समय में और दूसरा मंत्रि-परिषद में जाने के समय में। । जब तक विभागीय मंत्री का अनुमोदन नहीं होगा और मंत्रि-परिषद की स्वीकृति नहीं होगी, तब तक कोई विधेयक सदन में नहीं आ सकता है। यह जो बिल 2003 में आया था, यह इतना लंबा बिल है, व्यापक बिल है, एनडीए सरकार में आप थे, आपने आज जिन संशोधनों का उल्लेख किया है, इन संशोधनों को मैंने देखा है, इन तमाम संशोधनों पर तो उसी समय विचार होना चाहिए था। यह एक्ट 1924 का है, अब जब कई वर्षों के बाद इसमें संशोधन किया जाना है, तो आप जो सुझाव आज रख रहे हैं, इनको उसी समय में

आपको रखना चाहिए था, लेकिन आज इन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि यह बात मत कहिएगा। ...(व्यवधान)

महोदय, इस बिल को स्टेंडिंग कमेटी को भेजा गया। स्टेंडिंग कमेटी ने इसकी बहुत व्यापक तौर पर समीक्षा की है, कमेटी के पास बहुत सारे लोगों के रिप्रजेंटेशन्स आए, बहुत सारे लोगों की बातें कमेटी में सुनी गईं और तब जाकर कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया है। स्टेंडिंग कमेटी ने जो अनुशंसाएं की हैं, यह बहुत बड़ा बिल है, हो सकता है कि हमारी नजर न गई हो, 139 पेज का यह विधेयक है, हमारी नजर न गई हो, मगर स्टेंडिंग कमेटी की कुछ अनुशंसाओं का इसमें समावेश नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहूंगा कि बहुत अच्छी बातें सुषमा जी ने कही हैं, जो व्यापक लोकतंत्रीकरण की बात कही गई है और बिल में कहा गया है कि संविधान में जो 74वां संशोधन किया गया था जो स्थानीय निकायों के लिए और दूसरा संविधान के अनुच्छेद 43 में जो प्रोवीजन है 2 (ई) में, उसके आधार पर हम डीम्ड म्युनिसपैलिटी का दर्जा देंगे, कैंटोनमेंट का हम लोकतंत्रीकरण करेंगे, लेकिन बड़ा जबरदस्त विरोधाभास है और वह विरोधाभास यह है कि, इसमें अंतर्विरोध यह है कि लोकतांत्रिक स्वरूप बहाल करने और उसको व्यापक करने के बावजूद भी वह स्वरूप रह नहीं जाता है। और नौकरशाही के हाथ में, जो आर्मी के अफसर हैं, उसके हाथ में पूरा नियंत्रण रह जाता है। स्टेंडिंग कमेटी ने इस बात पर एतराज किया है।

महोदय, आप जो स्वरूप बनाएंगे और डीम्ड म्युनिसपेलिटी का जो दर्जा दिया है आपने, बोर्ड में सदस्यों की संख्या को आपने बढ़ा दिया है, सुषमा जी ने भी कहा है कि आपने बढ़ा दिया है, जनसंख्या के आधार पर आपने वर्गीकरण किया है और अभी आपकी जमीन 15 लाख हेक्टेयर बाहर थी, वह एनक्रोचमेंट में चली गई है, इसको एनक्रोचमेंट से कैसे आप मुक्त कराएंगे? जो अनधिकृत अतिक्रमण है, उसको कैसे मुक्त कराएंगे? इसका भी प्रावधान आपने इस विधेयक में किया है, लेकिन जो बोर्ड आप गठित करेंगे इलेक्टेड और नोमिनेटेड मैम्बर्स को बनाकर के, उसका जो निर्णय होगा, उस निर्णय को बदल दिया जाएगा या एक माह के लिए उसको स्थगित कर दिया जाएगा और फिर वह जाएगा कमांडिंग-इन-चीफ, द कमांड के यहां, विधेयक की धारा 56 में उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है-"If the President dissents from any decision of the Board which he considers prejudicial to the health, welfare, discipline or security of the Forces in a cantonment, he may for reasons to be recorded in minutes, by order in writing direct the suspension of action thereon for any period, not exceeding one month, and if he does so shall forthwith refer the matter to the General Officer, Commanding-in-Chief, the command." महोदय, यह जो व्यवस्था है कि जो वृहद लोकतंत्रीकरण आपने इस विधेयक के द्वारा किया है, उस सारे निर्णय को यहां मुल्तवी कर दिया जाएगा, निलम्बित कर दिया जाएगा, एक महीने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और फिर रेफर

हो जाएगा, जो कमांडिंग इन चीफ दि कमांड है, उसके यहां और उसका जो निर्णय होगा, वह अंतिम होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप म्युनिसिपेलिटी उसमें नहीं बना सकते हैं, कैन्टोन्मेंट एरिया है, आपने डीम्ड म्युनिसिपेलिटी का, समकक्ष का दर्जा दिया है, तो उसका निर्णय और निर्णय का कार्यान्वयन भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक सिर्फ देखने में ही न लगे, लोगों को महसूस भी होना चाहिए कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसका कार्यान्वयन हो रहा है। तो इसमें एक संशोधन करना चाहिए, जो उन्होंने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं, वैसे मैं बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, इस पर विचार करना चाहिए।

दूसरी बात जो सबसे अच्छी हुई है, बिल में पहले से प्रावधान था और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के नामांकन के लिए उन्होंने इसमें विशेष व्यवस्था की है। सरकार को और माननीय मंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जिन सदस्यों को इसमें आप नामांकित करेंगे, मनोनीत करेंगे, उनकी पात्रता क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका मानदंड क्या होगा और किस स्तर से ऐसे सदस्यों को आप मनोनीत करेंगे? इसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं मिला है, हो सकता है कि मेरी नजर से यह बात छूट गई हो। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब वे जवाब दें तो हमें बताएं कि अनुसूचित जाति के जिन सदस्यों को नामांकित किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, उनकी पात्रता यह होगी, मानदंड यह होगा और मानदंड तथा पात्रता के साथ-साथ सक्षम पदाधिकारी कौन होंगे, जो उनको नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे?

एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इलेक्शन आप करेंगे। वैसे सदस्यों के बारे में माननीया सुषमा जी ने कहा कि संख्या कम है, तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि जब आप एक बोर्ड बना रहे हैं और आपने एक श्रेणी बढ़ा दी है, केटेगराइजेशन आपने किया है, बढ़ा दिया है, तो सदस्यों की संख्या भी आपको बढ़ानी चाहिए। इसीलिए जब आप कहते हैं कि ग्रेटर डिमोक्रेटाइजेशन हमने किया है, तो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से और उसके कार्यान्वयन में किसी तरह का अंतर्विरोध न हो और वह एक व्यापक स्वरूप दिखाई दे, यह मैं अनुरोध करना चाहूंगा।

एक बात स्टैंडिंग कमेटी ने कही है कि जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा है कि एक साल में हम मतदाता सूची को बनाएंगे, जो असंभव है। कमिटी ने कहा है "The Committee note that under clause 31 the Central Government have been authorised to make rules and regulations for elections. However, no

authority has been mentioned which would initiate the process for holding elections to various contonments as and when these are due. The Committee desires that the Ministry of Defence should designate one of its officers as Election Officer, who would initiate the election process and supervise the conduct of elections in a free and fair manner. The clause should be amended accordingly." यह स्टेंडिंग कमेटी ने कहा है। तो स्टेंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, वह इस बिल में नहीं रखी गई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसको कैसे आप करेंगे, कौन अफसर होंगे, कैसे कंडक्ट होगा, इसके बारे में भी आप हमको बताएं अपने जवाब में। वैसे जो बिल है, वह बिल सुविचारित है और 1924 के बाद जो अव्यवस्था बनी हुई थी, वह व्यवस्थित होगी। 62 कैन्टोन्मेंट आपके है, जमीन रहने के बावजूद विद्यालय नहीं बन रहे, अस्पताल नहीं बन रहे, सुषमा जी ने उल्लेख किया। अत: इस नेक उद्देश्य से यह विधेयक यहां लाकर आपने अच्छा काम किया है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं।

एक बात का और मैं उल्लेख करना चाहता हूं, इस अवसर पर मैं प्रिविलेज लेना चाहूंगा कि दानापुर कैंट के बीचोबीच सड़क जाती है, हालांकि इस बिल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। तो दानापुर कैंट के बीचोंबीच सड़क जाती है और सड़क को कैन्टोन्मेंट के लोग रेगुलेट करते हैं। नतीजा यह होता है कि गाड़ी की स्पीड वे पांच या दस किलोमीटर फिक्स कर देते हैं। अगर कोई सीरियस पेशेंट है, उसे हृदयरोग अथवा कैंसर की कोई घातक बीमारी है, उसकी हालत बहुत खराब है, एमरजैंसी है, ऐसे में यदि गाड़ी पांच किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से चलेगी, तो मिलिट्री के लोग उन्हें पकड़ लेंगे और फिर उनकी जो दुर्दशा होगी, वह तो होगी ही।

सर, इसमें मुझे दो बातें कहनी हैं। कैंटोनमेंट की जो व्यवस्था है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है, वह तो अपने हिसाब से ही चलेगी। मुझे तो आपसे केवल दो आग्रह करने हैं। पहला तो यह कि यदि संभव हो तो जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, शायद एच.एच. के अंतर्गत है, आप उनसे बात करके यदि कोई फ्लाई ओवर इत्यादि बनवा सकते हों तो वह बनवा दीजिए। यदि यह संभव नहीं हो तो उस सड़क को ही आप कैन्टोनमेंट एरिया के बाहर की ओर से निकाल दीजिए। इसके कारण लोगों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है क्योंकि बनारस, आगरा, सासाराम और पटना से पश्चिमी बिहार में कहीं भी जाने के लिए, यहां तक कि औरंगाबाद होते हुए रांची या झारखंड जाने के लिए वह भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इसलिए, माननीय रक्षा मंत्री जी , मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सड़क दानापुर कैंटोनमेंट से होकर जा रही है, उस सड़क से होकर जाने के लिए जो गति सीमा निर्धारित की जाती है, उसके कारण जो परेशानी होती है, उसके लिए कोई न कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। आप सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एवं स्टेट गवर्नमेंट

से बात करके कोई रास्ता निकाल दीजिए, बिहार की जनता आपका आभार मानेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस बिल को लाने के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं।

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, there are so many welcoming aspects in this Bill, but there are some flaws also. My first suggestion is that it has the status of the deemed municipality and it is getting the benefit of that. As for the municipality, there is no reservation for women, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes here. This is my first point that I would like to make.

I am coming to the second point. Sir, in consideration of all these aspects, the Cantonment Act, 1924 was initially brought in. It was not self-sufficient and further steps had to be taken. At that time, the Cantonment Account Code, 1924, the Cantonment Fund Servants' Rule, 1925, the Cantonment Property Rules, 1925, the Cantonment Land Administration Rules, 1925 laws were brought in, but they were not sufficient. There is excess of land in the cantonment and without proper administration many lands have been leased out. So, there is no regular law even though we had four laws. So, I think, in order to regularize this, this Bill has been brought forward. This is not uniform all over India. The Cantonment Department was created under the Ministry of Defence. Earlier, the Cantonment officers were called Military Estate Officers, and now they are called Defence Estates Offices. Even now, coordination among the various wings of the administration, self-governance, matters of financial arrangement, management of lands are not properly regulated. The core issue in the old matter is that the democratic manner in the governance is lacking. Almost 17 lakhs acres of land is under cantonment, without proper administration. There is no uniform management of these properties. To eradicate the present problem, this Bill has been brought in, I think, Sir. However, Sir, I would like to point out that in Chapter III, it is said that the Cantonment Boards are created with four category of cantonments, and according to the classification of cantonments, the Board is constituted. In all the four categories, i.e., Category I, Category II, Category III and Category IV, the number of elected as well as Nominated Members is equal. It is mentioned that the Members of Parliament and the MLAs are Special Invitees to attend the meeting of that Board, but they are not having the power to vote. I also

want to mention that here simply 'the Member of Parliament' is mentioned. It is not specifically mentioned, it is not clearly mentioned whether that Member of Parliament will be from the Lok Sabha or the Rajya Sabha. Suppose, the Lok Sabha is dissolved. In that case, there will not be a representative of Parliament from a particular area, though that area has a Member of Parliament from the Upper House. Every Member of the Upper House is having his own nodal district. So, it should be clearly mentioned here that 'Member of Parliament' means 'Members of Parliament both from the Upper and Lower House'. Sir, I request that this has to be changed. There is also no clear view with respect to clause 12(9).

Sir, under Section 319 Schedule IV, various offences are enumerated wherein the power is given to the Police official to arrest a person committing breach of any of the provisions of this Act, which are specified in Schedule IV, without warrant. But the offences mentioned in the Schedule are: begging, beating drums, singing, etc. It was mentioned that they could be arrested without issuing any warrant.

I would also like to mention that offences under Section 183(1) and 304(a) are highly arbitrary and look very inhuman. Both relate the same thing. A civilian can go not only to the military hospital, but he can also go to any hospital as per his wish. However, according to Section 183(1) he is compelled to go to that particular hospital. Otherwise, he would be arrested without any warrant. So, it should be cleared and it should be amended.

Sir, the Standing Committee in its recommendations had said that issues like greater democratization, better financial management and Centrally-sponsored schemes in the cantonment have not been taken into consideration. The Committee has also expressed its apprehension on the wide powers given to the CEO, and the worst part of it is that there is no appellate authority against the decision of the CEO. There is no provision of appeal against the decision of the CEO. Sir, the purpose of this Bill is to create democracy. But, Sir, when one sees this part of the Bill, one finds it autocratic, because as per this provision, the CEO can decide on his own, and there is no provision of appellate authority. So, I think, there should be a provision of the appellate authority against the decision of the CEO to have a fair decision. Sir, I have already

mentioned that the Bill is brought for greater democratization of the Cantonment Board. There is no provision of appeal against the autocratic order of the CEO. Sir, I am stressing upon this point again. It may be looked into.

Anqther irony of the Bill is clause 108 which says that the Cantonment Board is a Deemed Municipality. This is a point which I made at the initial stages of my observation that the Cantonment Board is a Deemed Municipality. However, there is no provision of reservation of seats in the Cantonment Board for the women, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. It should be taken care of. Though the Committee has recommended for that, the Bill has been brought here without any change or amendment. So, it should be considered and the aspect of reservation for women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be included in the Bill.

Sir, we are at a stage when we are following the norms of Panchayat Raj. Now, if you call the municipality a democracy, then we should have provision for the reservation of seats for women and Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. So, it should be considered.

Sir, the another point is, the elected members and the nominated members sit together and take a decision with regard to a particular matter. But if the elected Members wish, the final decision taken with regard to a particular matter, can be changed at any time. It is a very big flaw in this Bill. They sit together and take the decision, but ultimately, even though the nominated members are part of the decision-making process, the full Board may be changed at any time. The nominated members have such powers. So, these types of flaws should be rectified and it should come in full form. I would like to particularly stress upon the point that there should be reservation for women and SCs and STs.

Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

SHRI SHYAM BENEGAL (Nominated): Sir, I have a very short intervention to make. In the substitution given by the hon. Defence Minister in Clause 64, there is a sentence that reads, 'conservation and maintenance of ancient and historical monuments, archaeological remains and places of public importance in the cantonments'. I feel that heritage sites should also be mentioned here, for the simple reason that

there are many places. For instance, the Ahmednagar Fort Jail, which is actually a barrack, was a jail in the 1940s where our national leaders were incarcerated. There are several such places in various cantonments of India.

There is also another place where 'conservation' has been defined. And this conservation has been defined for purposes of Clause 17. I think, it should apply in every place where conservation is mentioned as far as Bill is concerned.

I don't think I have anything more to say because I feel otherwise it is an excellent Bill. Thank you very much.

**श्री नंदी येल्लैया** (आंध्र प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो कैंटोनमेंट्स बिल में संशोधन आया है, यह देर आयद दुरूस्त आयद है। मैं समझता हूं कि पिछले 9 साल से कैंटोनमेंट्स के अंदर चुनाव नहीं हुए हैं, पूरे भारत के अंदर 64 केटोनमेंट्स हैं। इसमें ''ए'' क्लास कैंटोनमेंट्स ''बी'' क्लास कैंटोनमेंट्स और ''सी'' क्लास कैंटोनमेंटस हैं। ये तीन टाइप के कैंटोनमेंट्स हैं, जो पूरे भारत में काम कर रहे हैं।

सर, मैं कैंटोनमेंट्स बोर्ड में पाच बार लोक सभा के सदस्य की हैसियत से मेम्बर रह चुका हूं और मुझे इसमें काम करने का तजुर्बा है। कैंटोनमेंट्स बोर्ड का चेयरमैन ब्रिगेडियर होता है, इनको सिविलियन्स के डेवलेपमेंट की कोई जानकारी नहीं होती है। मैं समझता हूं कि नगरपालिका, में जैसा आपका सिस्टम है, उसी के अनुसार वाइस चेयरमैन का भी इसमें चुनाव होना चाहिए। अक्सर सिकंदराबाद कैंटोनमेंट्स में जिस किसी भी ब्रिगेडियर की पोस्टिंग होती है, वह रिटायरमेंट के आसपास ही होती है, उस समय उसको इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि सिविलियन्स को सिविक एमिनिटीज़ मुहैया कराई जाये। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं, उस वक्त श्री सी.पी.एम. सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त कैंटोनमेंट्स बोर्ड के हर दो साल में चुनाव होते थे। उस समय के राज्य सभा के एम.पीज और लोक सभा के एम.पीज ने मिलकर एक रिप्रजेंटेशन दिया था कि ग्राम पंचायत का म्युनिसिपल कारपोरेशन की तरह कार्यकाल पांच साल का किया जाये। उसके बाद इसके कार्यकाल को 2 साल से 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। दूसरे कैंटोनमेंट में डेवलपमेंट्स के लिए उस जमाने में कोई फंड नहीं होता था। रिपेयर और मेंटेनेंस फंड के सिवाय दूसरा कोई फंड नहीं होता था। जब पी.वी. नरसिंह राव, was the Prime Minister, और आंध्र प्रदेश के श्री मल्लिकार्जुन राव आपके State Minister थे, उस वक्त हमने रिक्वेस्ट की थी। वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम थी। डेवलपमेंट्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। उस जमाने में सर्विस चार्जिज सिकन्दराबाद कैंटोनमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाने से, मैं समझता हूं कि वहां काफी तरक्की हुई है। इवके अलावा एसपीएस ड्रेनेज का काफी फायदा हुआ। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सिकन्दराबाद के अंदर कैंटोनमेंट की जो मशीनरी

है, जो आपकी इंजिनियरिंग है, जो आपकी टाउन प्लानिंग है, जो एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ये तमाम लोग क्या करते हैं, यह भगवान ही जाने। वन प्लस वन से कैंटोनमेंट के अंदर बिल्डिंग्स बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप एक रक्षा मंत्री की हैसियत से हमारे साथ मत आइए। मेरे पीछे बैठे राज्य सभा के मैंबर के केशव राव जी के साथ मत आइए। सरप्राइज इंस्पेक्शन आप वहां पर करिए, न आप ब्रिगेडियर को बोलिए न किसी और को। कितने अपार्टमेंट्स बन चुके हैं-अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन से। यह सब क्यों हो रहा है? आपके तमाम लोगों के रहने के बावजूद भी मैं समझता हूं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, किसी बिल्डर की शिकायत नहीं कर रहा । हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस सिस्टम को इनीशियल स्टेज पर रोकना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से ये अपार्टमेंट्स बने, जस्ट लाइक मुम्बई। मैं समझता हूं कि यहां पर जो ऑफीशियल्स बैठे हुए हैं, उनको मालूम होगा कि कैंटोनमेंट किस हालत में है। मैं आठ बार लोक सभा के लिए लड़ा हूं। पांच बार मैं लोक सभा में था। मैं एक अथॉरिटी के साथ यह सब बोल रहा हूं। दूसरा, बहुत से ओपन लैंड्स हैं। आपका हर डिपार्टमेंट यह कहता है कि यह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? What is the purpose? किसलिए होना चाहिए? बलारम एक ऐतिहासिक स्थान है, बलारम से गांधी अस्पताल तक दस किलोमीटर का डिसटेंस है। अगर कोई पेशेंट सीरियस है तो वहां पर आने के लिए काफी दिक्कत होती है। हमने आंध्र प्रदेश की सरकार की तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमें अस्पताल के लिए लैंड चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पैसे नहीं चाहिए, फाइनैंस नहीं चाहिए, आंध्र प्रदेश सरकार उसे बनाना चाहती है, लेकिन उसके बारे में कोई रिसपांस नहीं है। डिफैंस का हरेक आदमी यह कहता है कि यह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका कोई कारण नहीं है। सर, ऐसी बहुत सी बातें हैं। रक्षा मंत्री जी, आप तो बहुत सीनियर मंत्री हैं, आपको हर चीज़ की जानकारी है। हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, आपको हर चीज़ की जानकारी है। लेकिन ये तमाम कमियां वहां पर हैं। दूसरा, कैंटोनमेंट के अंदर, वहां से जो लोक सभा के मेंबर चुनकर आते हैं, वे एक्स ऑफिशियों मैंबर नहीं हैं। जब मुलायम सिंह जी डिफैंस मिनिस्टर थे, उस वक्त मैंने एक रीप्रेज़ेंटेशन दिया था। मैंने कहा था कि उनको आप रखिए। एमएलएज़ को एक्स ऑफिशियो मैंबर रखिए, एमपीज़ को रखिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कम से कम आप इस पर ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। 9 साल से कैंटोनमेंट चुनाव नहीं हुए हैं। महोदय, मैं रक्षा मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी से कहना चाहता हूं कि सिकंदराबाद कैंटोनमेंट के बारे में अखबार में आया कि अभी वहां चुनाव हो रहे हैं। सिर्फ एक ही जगह चुनाव हो रहे हैं, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट के, बाकी जगह चुनाव नहीं हो रहे, क्योंकि एक्ट अमेंडमेंट के लिए पेंडिग पड़ा हुआ था। वहां पर नॉमिनेट करने के बाद, कभी गलत बोलकर कोर्ट में गए। कोर्ट-कचहरी हुई, कई बार हुई। बहुत लम्बा सफर चले। उसके बाद कोर्ट की डायरेक्शंस थीं कि उसका चुनाव करना है। 64 कैंटोनमेंट में से एक ही कैंटोनमेंट, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट का

चुनाव हो रहा है। अखबार में हमने पढ़ा है। मंत्री महोदय, मैंने सुना है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका के, वहां पर लेडीज़ का रीप्रेज़ेंटेशन नहीं है। इस एक्ट का अमेंडमेंट, यह पास होने के बाद, 6 महीने के बाद क्या फिर से सिकंदराबाद कैंटोनमेंट का चुनाव होगा, यह मैं आपसे क्लैरीफिकेशन चाहता हूं। ये तमाम चीज़ें हैं। बहुत से कैंटोनमेंट में मैरिज हॉल्स बनाए हैं, वे किनके हैं? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। लोग पैसे से पैसे कमा रहे हैं। कमाओ, हरेक आदमी के बस की बात नहीं है। वह भी देखना चाहिए। पैसा कमाना भी हर एक की बस की बात नहीं है। बहुत से लोग दौलतमंद होते हैं फिर लक्ष्मी किसके पास रहती है? लक्ष्मी तो कुछ लोगों के पास ही रह सकती है। आज आप देखिए कि आप कैंटोनमेंट में अपार्टमेंट या मैरिज हॉल निर्माण का जो चाहे काम कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, आपका लोक सभा के लिए इनता प्रचार नहीं होता है, जितना आपका कैंटोनमेंट के लिए होता है, यह सब क्या है? उन्होंने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड मैम्बर को एक सिटिंग फीस भी नहीं मिलती है, फिर आप क्यों इसका चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने कहा कि यह अन्दर की बात है। सभी लोग समझते हैं कि यह अंदर की बात है, What is the cantonment election? मैंने 6 साल कैंटोनमेंट इलैक्शन लड़ा है और मैं सब जानता हूं। मैं, मंत्री महोदय, से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं, जिनको कन्फीडेंशली देखना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें आप ही सुधार ला सकते हैं। आपके पास वह कैपेसिटी है, आप सुन सकते हैं। लेकिन आज आप कैंटोनमेंट के अंदर जो चाहे ले सकते हैं। वहां सवेरे से लेकर शाम तक की पूरी फाइल आ सकती है क्योंकि वहां पर एक-एक जगह काम होता है। वार्ड नम्बर-4 में 18 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं और कुछ जगह 20 उम्मीदवार हैं। एक वार्ड के अंदर एक-एक आदमी करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। वहां कैंटोनमेंट के अपार्टमेंट हैं और वहां अभी भी 7 वार्ड्स हैं। जब मैं लोक सभा में था, मैंने सर्विस चार्जिज दिलाए थे। जहां कहीं पर पानी की किल्लत थी, तो मैंने मल्लिकार्जुन, स्टेट मिनिस्टर की वहां पर विजिट कराई थी। आपके ब्रिगेडियर और आफिसर्स और नॉन आफिसर्स की एक बैठक भी हुई थी। उसमें काफी फंड्स दिए गए थे, लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है, इसके पीछे लोग इस तरह से पड़े हुए हैं कि पता नहीं इसमें क्या है? आपको तो मालूम है सिकन्दराबाद के एक नोमिनेटिड मैम्बर थे, उनको एक साल लग गया और उसमें कई डिफिकल्टीज आई थीं। आखिर में, उसको मजबूर होकर चुनाव करना पड़ रहा है। अभी 6 तारीख को पोलिंग है, तो मैं रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसको सुधारिए। डेमोक्रेसी के अंदर मैं जो चाहे कर सकता हूं, किसी के बल से, किसी के पैसे से, लेकिन किसी इंडिविज्युअल ताकत से तो वह नहीं हो सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर एक सिस्टम होना चाहिए। जो आपके लॉज हैं, जो आपके बॉय लॉज हैं, जो आपका सिस्टम है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह बहुत बुरी बात है। नहीं तो लोग बोलेंगे कि साहब यह कैंटोनमेंट है, इस पर बात मत करो। यह बहुत बुरी हालत में है क्योंकि मुझे तजुर्बा है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको सुधारिए और देर आयद दुरुस्त आयद। क्या यह सही है और

कहां तक सही है। इस एक्ट के आने के बाद क्या सिकन्दराबाद का चुनाव होगा? अखबार में आया है कि होने वाला है। महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि सिकन्दराबाद की कैंटोनमेंट के बारे में बहुत सी चीजें हैं, वहां एक एरिया तिलमुलगिरी है, यह सील एरिया है और सिटी के बहुत करीब है। अभी हमारी माननीय सदस्य श्रीमती दुर्गा जी बोल रही थीं कि एक लॉंग प्रोपोजल था और उस जमाने के चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ लैटर लिखे थे। वह हो गया। अम्बाला में जो हुआ, पंजाब के अंदर दो-तीन कैंटोनमेंट को म्युनिसिपैलिटी को हैंड-ओवर किया गया। यह भी लॉंग टर्म से पेंडिंग था और डी॰ नरसिंह राव जिस वक्त मिनिस्टर थे और मैं जब एमपी था, उस वक्त भी, कांग्रेस की सरकार थी। डा॰ चेन्ना रेड्डी के जमाने में ये तमाम बातें हुईं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सुधारें और जल्दी अमेंडमेंट एक्ट को लाएं। इसके बाद महिलाओं के कोटे का मसला भी अधूरा पड़ा हुआ है, उनको मौका दीजिए। मैं इतना ही कहते हुए, अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, यह बिल 2003 में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने पार्लियामेंट में पेश किया था। हमारे बंधुओं ने यह कहा कि उस समय इस बिल की खामियों को क्यों नहीं देखा? मैं कहना चाहता हूं कि आपने भी नहीं देखा होगा क्योंकि मंत्रियों को उसको बारीकी से स्टडी करने के लिए समय ही नहीं मिलता। जब से हमारे देश में यह कमेटी व्यवस्था चली है, इस कमेटी व्यवस्था के अंतर्गत, पार्लियामेंट के सामने जो भी विषय आते हैं, उनमें से बहुत से विषय कमेटी को रेफर कर दिए जाते हैं, कमेटी बड़ी बारीकी से उनको देखती है और उसके आधार पर उन विषयों को शामिल किया जाता है। इस विषय पर जो स्टैंडिंग कमेटी बनी, उसने 10 मई, 2005 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। जब वह रिपोर्ट आ गई, तो उसके आधार पर मंत्री जी का यह कर्तव्य था कि स्टैंडिंग कमेटी की कौन-कौन सी सिफारिशें इस बिल में हैं, अगर उनको उस समय आप बारीकी से देखते, निश्चित रूप से बहुत से अमेंडमेंट्स आज आप पेश कर रहे होते और स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव भी इसमें शामिल हो जाते।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस बिल को वापस ले लें और इसमें जितनी खामियां हैं, उनको ठीक करके दोबारा अगर बिल लाएंगे, तो अच्छा होगा और इसमें अधिक समय भी नहीं लगेगा, वरना फिर से आपको इसमें अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे, ऐसा आप स्वयं महसूस करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 1924 का जो छावनी बिल था, उसको हम रिपील कर रहे हैं और यह नया बिल आप उसी के स्थान पर ला रहे हैं। पिछले 7 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। हमारी 62 छावनियां हैं, उनके चुनाव 7 सालों से नहीं हुए हैं। उनके चुनाव जल्दी हों, इसमें कोई संदेह नहीं

है। इस बिल में यह बात कही गई है कि इसमें हम वृहत्तर लोकतंत्र की व्यवस्था कर रहे हैं, एस॰सी॰, एस॰टी॰ और महिलाओं के लिए हम आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं और बेहतर वित्त प्रबंध हो, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्षेत्रों का विकास तेजी से हो और रक्षा भूमि का प्रबंध ठीक प्रकार से हो–आपने अपने बिल में ये उद्देश्य बताए हैं। ये बहुत अच्छे उद्देश्य हैं, लेकिन जैसा हमारी बहन सुषमा जी ने कहा कि इसमें जो बहुत सी खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने की नितांत आवश्यकता है। उस कमेटी को कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। कोई भी प्रस्ताव अगर पारित होगा, तो कमेटी का अध्यक्ष उसको null and void कर देगा और ऊपर भेज देगा। लोकतंत्र में इतना बड़ा गलत काम हो, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसी तरह इस बिल में व्यवस्था है कि अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, नॉमिनेशन होगा, यह भी बड़ी खराब व्यवस्था है। निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन होना चाहिए और इसमें जनप्रतिनिधियों का बहुमत निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधियों का बहुमत नहीं है, तो कैंटोनमेंट में लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 117 लाख एकड़ भूमि रक्षा विभाग के लिए है, उसमें से केवल 15 लाख एकड़ जमीन ऐसी है, जो कैंट के इलाके के अंदर है, बाकी की जमीनें डिफेंस के पास हैं और जैसा अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि उस पर बहुत से encroachments हो रहे हैं और उसका दुरुपयोग हो रहा है। यदि हम इस ओर ध्यान देंगे, तो यह दुरुस्त हो सकता है। निश्चित रूप से यह जो बिल पेश हुआ है, इसकी 365 धाराओं को पढ़ना बड़ा कठिन काम है। मैंने बड़ी मुश्किल से एक-दो घंटे इसको देखा, लेकिन ज्यादा समय नहीं देख पाया, तो आप तो शायद देख ही नहीं पाए होंगे, आपने तो शायद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं देखी होगी, जैसा बिल आया, वैसा ही आपने पेश कर दिया है और उसमें आज बहुत सी खामियां हैं। इन खामियों को दूर करने के लिए मैंने सुझाव दिया है कि आप इस बिल को withdraw करके, फिर से ले आएं, तो शायद बहुत अच्छा होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं, उनको इस बिल में शामिल करते हुए फिर से इस बिल को लाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल पर पुनर्विचार होना चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री वीरेन्द्र भाटिया** (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, हम 2003 का बिल 2006 में 3 वर्ष के बाद डिसकस कर रहे हैं। यह सराहनीय प्रयास है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें कहीं, इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

सबसे पहली बात यह है कि हम जब बात करते हैं कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन जैसा कि इन्दिरा जी ने कहा कि इस बिल में कहीं भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा सुझाव है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जैसा सुषमा जी ने कहा कि हम जनतंत्र की बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जनतंत्र के लिए हमने यह बिल लाया है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो सके, जनता के द्वारा चुने हुए बोर्ड का गठन हो सके, लेकिन जब इसके सेक्शन पर दृश्य डालें, तो यह मालूम होता है कि निर्वाचित सदस्यों से अधिक नामांकित या पदेन सदस्यों की संख्या है। मैं समझता हूं कि पदेन सदस्यों की संख्या से अधिक निर्वाचित सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। यह मेरा दूसरा सुझाव है।

**(श्री उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)**

तीसरी बात यह है कि जैसा कहा गया कि पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। सुषमा जी ने एक प्रश्न उठाया था। मैं समझता हूं कि पदेन सदस्यों को भी मत देने के अधिकार की व्यवस्था इस बिल में होनी चाहिए।

एक महत्वपूर्ण बात जय प्रकाश अग्रवाल जी ने उठाई थी कि जो नागरिक लोग कैंट की सम्पत्ति में रह रहे हैं, जो सैनिक नहीं हैं, उनके बारे में क्या स्टेटस होगा, जिन्हें लीज़ पर कैंटोनमेंट बोर्ड की सम्पत्ति दी गई है, इसके बारे में उनका स्टेटस क्या होगा, इसकी भी इसमें व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे उनके मन में संशय की भावना न रहे।

मैं समझता हूं कि 3 वर्षों के बाद यह बिल पेश हुआ है, लेकिन अभी भी यह अपूर्ण है। यद्यपि एक अच्छा प्रयास क़िया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूँ, अपनी पार्टी की ओर से भी समर्थन करता हूँ, लेकिन जो 3-4 बातें कही गई हैं, अन्य सदस्यों की ओर से भी जो सुझाव आए हैं, मैं उनका समर्थन करते हुए कहूँगा कि उन सुझावों को भी इसमें सन्निहित कर लिया जाए। धन्यवाद।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Deputy Chairman, Sir, first of all, I would like to express my gratitude to all the hon. Members who participated in the debate and made their valuable contribution on the various provisions of the Bill. While initiating the discussion, Sushmaji elaborately developed certain points, most of those points I will cover in the course of my reply. But before that, I would like to remove one misconception which I think some hon. Members might have. It is not just creation of a municipality. That is why you have used the words 'deemed municipality.' If it were a municipality, or if it were any other local body, perhaps there would not have been any need of bringing this Bill. Cantonment in the Act of 1924, when the Act was printed, it was very beautifully put—I do not know whose idea it was—that dictionary meaning of 'cantonment' is the 'temporary quarters of the troops.' Later on, those temporary quarters of the troops became permanent quarters

**5.00 P.M.**

of the troops. The first cantonment was created in 1758 in Barrackpore, in Bengal. Second cantonment, which hon. Member Mr. Mangani told, was in Danapur, which was created in 1768. And you take your mind to about 200 or 300 years ago, veering round this cantonment, urbanisation took place, and it was thought, in cantonment which was basically meant for the civic amenities of the troops who were stationed there, certain civic amenities are to be provided so that their health conditions, habitat conditions, remain perfect so that they are in a fit position, in a fighting position. But as it happened in course of development of civilisation, growth of civilisation, veering round this cantonment, some sort of urbanisation took place; and people found that there are better civic amenities in the cantonment area. Therefore, many people who did not have anything to do with military also started living there. You go back to the history and there are the problems which quite a number of hon. Members have referred to like lease right, grants, etc. I am also flooded with a series of representations and letters from the MPs. Two hundred years ago, 150 years ago, 90 years ago, there were various ways of transfers. So, it was thought necessary and out of the 62 cantonments, only six cantonments were established after Independence. 56 cantonments were established before the Independence, during the British days. It was thought whether we can provide better civic amenities to these cantonments and while providing better civic amenities, whether there should be military representation of the elected component. If the idea was to convert each cantonment into municipality, then, there was no need. Cantonment is basically meant for the location of the troops. Therefore, the predominance of the military interest is to be there. It is not my intention to create another local self-body. Enough municipalities are there. With urbanisation, there would be more; the trend of industrial development is more and more urbanisation and the problems are also coming. Even I received some recommendations that as the township grew, development took place veering round the cantonment; land prices of the cantonment are also very high. So, some suggestions are coming to me that you locate your cantonment outside the busy areas of the city so that these could be utilised more effectively commercially because the land prices are very high. But equally, I should have my problems because I am to locate such a huge number of Armed Forces in different cantonments. It is not simply possible. But, to provide the civil amenities,

we have thought that certain measures are to be taken. But, if you consider that it is a handicap, if you consider that it is a deficiency, most respectfully, I will submit that this deficiency, this handicap, is inherent in the system because it will have to be under the command and under the control of the Station Officer. There is no other way. But within that, what type of arrangements we can make, we thought of. It is not correct to say that I have ignored the recommendations of the Standing Committee. Some hon. Member criticised that I have not even studied it. The Members have the privilege of coming to that type of conclusion, but those who know me will know that I am not new in this job. From 1970s, I am in the Government and the first lesson that one of my officers, a civil servant, taught me that if you want to learn something, read the file from the noting of, at least, the Deputy Secretary, if not, the Under Secretary. And till date, I have developed that habit. That is why, when a smart Minister can dispose of a file in 5 minutes, I take, not 50 minutes, but, at least 15-20 minutes because, that is in-built in my habit. So, please do not be under the impression that I have not studied it. But, it is equally true that I have not accepted all the recommendation. Out of 92 recommendations, I have accepted 42 recommendations. I have accepted one of the major recommendations about which many of you commented, that is, what is to be done about the development of 15 lakh acres of defence land. But surely, I would like to tell you that there should not be any illusion on this score because I am not going to hand over these lands to the promoters to construct the high rise buildings and complexes because the defence requirement is to be kept in view, and whatever is needed, we will be doing that. It is not correct to say that whenever the requirement of the society comes or the developmental proposals come, we do not accept them. Just on 23rd, I was in Pune, sitting along with the local MP and the chairperson of the Municipal Corporation, for the construction of roads, for the link roads and for the development of airport. There, along with my officers, I took the decision. Delhi Metro Rail is substantially on the defence land. For the Bangalore development projects, substantially, we are giving the defence land. That is why a decision was taken, and I do consider very correctly taken in 1990, not long ago, that even if a small piece of defence land is to be transferred, it is to be decided at the level of the Cabinet, not at the level of the Defence Minister, and I do feel that it is a very judicious decision. Otherwise, in the days of land grabbing, I am sorry for using this phrase,

perhaps, you would have been confronted with a situation that all the prime lands have gone.

Coming to the observation which Sushmaji made that why didn't we do it? It is not that we wanted to create full-fledged municipalities. That is why we kept it like this, 8 nominated members and 8 elected members. Certain hon. Members made their observations that is why you are not making the reservations. It is one of the reasons why it has taken so much time. Right from 2003 to 2006, reasons are obvious. In 2003, the Bill was introduced here. After that, Lok Sabha was dissolved in 2004. Thereafter, new Standing Committees were constituted, and Bills were referred to them. They submitted their report. In 2005, we could have passed that Bill. In the last Session, I introduced the Bill. But, Sushmaji has very correctly pointed out that it is a voluminous Bill. There are 365 clauses, 5 schedules, and a large number of amendments are there. Therefore, it will take time. That is why some time has been taken. I need not make any comments because, you know, nowadays, you do not get much time for the legislation. A lot of other issues are keeping Parliament engaged. But, then, for reservation, we have provided clause 31. I have not mentioned that. But, if you read clause 31(d), you will find that the Government will, by rules, divide the cantonment areas in wards, and reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women will be made by the rules. A provision has been made in clause 31, sub-clause (d). Therefore, that is one aspect which we thought is needed. In regard to the provision for certain facilities which are to be created, I don't say that in all cantonments, we have been able to provide certain facilities which are desirable. But in most of the cases, the election could not take place because of the simple fact that we were hoping that the Bill would be passed and once the Bill was passed, the reservations would also be there and we would hold the elections.

My friend, Yelliaiah Nandiji, was talking of the election in the Secunderabad Board. It is because of the High Court direction. The election has to take place; election will take place, and after that, we will seek the advice of the High Court. If they say that 'you should hold elections under the new Act', we will have it. The problem is that there cannot be any readymade solution in respect of the properties which they are holding in these civil areas because these are all related to the titles. Whatever decision we may take, even the cantonment boards say

that it is not binding because people will go to the court, and Members are fully aware of how much time a court takes to resolve the different issues so far as the title is concerned.

Some comment has been made why you are not giving the power to the Board itself to impose the taxes. For very obvious reasons. We want development. And excuse me, as an old hat in the Ministry of Finance, I do always feel that taxation can be done. Though the basic principle of parliamentary representation is 'no taxation without representation', the fact of the matter is, people's representatives are always subjected to tremendous pressure because taxation is the most unwelcome job of the people, which is to be undertaken by the representatives. That was why, once a prince has pointed out that a prince should always remember that a man can forgive the murderer of his father, but a man cannot forgive a person who forfeited his property. Therefore, I do feel that if you give the right to impose taxes on the elected members, and if a cantonment is having 20,000 people and eight members--and each elected member will be known to the electorate--it would be extremely difficult for him to take hard decisions. But for development, we require them. And I say, and very frankly I have admitted, that it is not full democratisation. It was to better an arrangement, which we have had earlier, by enhancing the number of members, by having the elected Vice-President, and if theoretically 'yes', provision is there. But hardly any board has been superseded in the contemporary period. I checked up from the officers; no supersession has taken place in the recent period. Therefore, with taxation, we thought, it would be better to keep it up.

Concerning clause 97, I request Sushmaji to bear in mind that on this clause, there is no recommendation of the Standing Committee. The order of a District Court confirming, setting aside or modification of an order in respect of any valuation or assessment or liability to assessment or taxation shall be final because some finality is to be given and I don't think that there is any justification for removing the appeal.

Clause 67 is for fees. Fees are not taxation. Fees are collected for providing certain services. In respect of taxation, clause 66, I have already stated that it has provided a sound base for the financial health of the Boards. We have noted that there are certain Cantonments Boards which are financially weak and there are certain Cantonment Boards which

are financially sound. So, we felt that, instead of depending on the Government, there should be a provision for cross-subsidisation. Recently I have gone to one of the Cantonments, the Barrackpore Cantonment, for a formal inauguration. There I was pleased to see that from the Cantonment Board fund they have provided drinking water facilities not only to civic areas within the jurisdiction of the Cantonment Board but also to 9,000 people outside the Cantonment Board. They are getting benefit out of it. This is possible. Not a single rupee has been taken from the State Government or from the Union Government. They even did not charge it from the Defence. We are not to spend much on the Cantonments.

Shri Shyam Benegal has raised a very valuable point about the heritages. We have made provision in clause 164. That will also be taken note of. Apart from that, some of the buildings, furniture, paintings—Sushmaji is aware of it-in the old Cantonments are being simply destroyed. I have asked my officers, as quickly and as fast as possible they can, to procure them and preserve them. If they can't preserve them, let them be transferred to those who can preserve them because these are national heritages. We must have them. Normally, the Army maintains them better than the civilian population. That is also a fact. But still, if we find that they could not be properly protected, we should make some arrangements for their proper upkeep.

Mr. Deputy Chairman, I have already replied to certain other points. Now we have increased the number. But I must say that it is not adequate. If you compare it with the electoral ratio, it is much less. Compared to the Municipalities and big Corporations, the electorate and the elected ratio in the Cantonment Boards is much favourable becuse the total number is increased from 341, as per the existing Act, to 392. I have already mentioned about women representation.

I have stated that out of the 95 recommendations of the Standing Committee, I have accepted 42 recommendations. I don't say that this Bill is foolproof. There may be certain lacunae. There will be no problem. As and when we implement the provisions of this Bill, after putting them into operation, if we find that it requires certain amendments and corrections, surely, we will be able to do them.

In respect of the problem which the former Mayor of Kolkata Corporation

and my old friend, Prasantababu, referred to, it is a genuine problem. Here also it is reciprocal. But we have taken it up that, at least, the municipal body should be compensated, if they can't collect revenue from Central properties as property tax. This issue, of course, is a larger issue.

Another point which has been referred to is regarding the thoroughfare through the Danapur Cantonment. Though it is not within the purview of this Bill, surely. I will discuss this problem with my colleague in the Ministry of Surface Transport. Perhaps the best course would be to have a bypass because a town has developed through that area. Therefore, in some areas, we are helping them by providing lands. But if it is too long a stretch, then, it becomes a problem from the security point of view also. Nowadays, nobody knows what would happen at what point of time. Therefore, the best course would be to have a bypass. In certain areas, we are having it because over the years, urbananisation has taken place around the Cantonments.

With these words, I request the hon. Members to lend their support to this Bill.

**श्री मंगनी लाल मंडल** (बिहार): उपसभापति महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दानापुर कैन्टोनमेंट की सड़क की समस्या के बारे में अनुरोध किया था, उस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था। वह सड़क जो बीचों-बीच से जाती है...(**व्यवधान**)

**श्री प्रणब मुखर्जी:** मैंने इसीलिए तो कहा था ...(**व्यवधान**)

**श्री मंगनी लाल मंडल** (बिहार): नहीं इस मामले में आपने कोई चर्चा नहीं की, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं।

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** I just told you that I would take it up with my colleague, the Minister of Surface Transport. The first thing I mentioned about it...

**श्री नंदी येल्लैया:** डेपुटी चेयरमैन सर, एक क्लैरिफिकेशन है ...(**व्यवधान**)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has given all the information in detail. What else do you want?

**श्री नंदी येल्लैया:** सर, मैं रक्षा मंत्री जी से यह क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि सिकन्दराबाद कैन्टोनमेंट के अन्दर 1924 में जो ऐक्ट बना था, उस जमाने में बलारम में पब्लिक यूटिलिटी के

लिए एक हॉस्पिटल बना था। लेकिन आज समाज के अन्दर देखते हैं कि जिनके पास पैसा है, वही लोग नर्सिंग होम में इलाज करवाने के लिए जाते हैं। मैंने वहां एक अस्पताल बनाने की इच्छा की थी आज से दस वर्ष पहले, मैं आपसे डिफैंस की लैंड नहीं मांग रहा हूं, जो ऐक्सैस लैंड है, जिसका डिफैंस से कोई ताल्लुक नहीं है और जो ऐसे ही पड़ी हुई है, वहां पर एक हॉस्पिटल बनाने के लिए मैं जगह की मांग रहा हूं। बलारम से गांधी हॉस्टिपल आने के लिए ग्यारह किलोमीटर का रास्ता है, कई बार सीरियस केसिज़ भी होते हैं। मैं रक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां पर ऐक्सैस लैंड है, उसे आप किसी और इंस्टीट्यूशन को मत दीजिए। मैंने स्पेसिफिकली सिकंदराबाद कैन्टोनमेंट की बात की है ...(व्यवधान)।

श्री उपसभापति: वह तो बता दिया है न ...(व्यवधान) इन्होंने यह बता दिया था।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, you would appreciate that it is not possible to answer individual problems of all the 62 Cantonments. But whenever any developmental proposal comes from certain areas, we will look into it and, if possible, we will do it. In this case also, I will consider it.

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Sir, what I am going to raise is a general issue. I have a small doubt which the hon. Minister can clarify. In clause 12 (9) at Page 8, it says, "The Member of Parliament and Member of Legislative Assembly representing constituencies which comprises wholly or partly the cantonment area..." I would like the hon. Minister to clarify as to whether the Member of Parliament includes a Member of the Lok Sabha or a Member of the Rajya Sabha or both.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Of course, it is the Lok Sabha Member because cantonment is located in a territory, and territory comes within a territorial areas of a Member of the Lok Sabha. The Members of Rajya Sabha do not have any territory.

SHRI N. JOTHI: You had been a Member of the Rajya Sabha for a long period ....*(Interruptions)* We have got a nodal district...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We have stated, "representing that constituency where the cantonment is located."

SHRI N. JOTHI: I would request the hon. Minister to consider including Rajya Sabha Members who are residing in that locality ...*(Interruptions)* I am not speaking for myself. I am not residing in any cantonment area. Even if I happen to be there, kindly exclude me from

that. I am only saying it as a general case. In times of dissolution of the Lok Sabha, inclusion of a Rajya Sabha Member can be considered. That is No. 1, Secondly, in Schedule IV at Page 113, "Cases under which police may arrest without warrant", in clause 289 (1) (a) (v), you have mentioned 'begging'. You kindly look at the description given here. My Lord, have you got it? ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, have you got it?

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh) Sir, he has just come out of the court ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Sorry, Sir. ...*(Interruptions)*... Quite often, I make such mistakes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He forgets that he is in Rajya Sabha. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Sir, please look at 289(1)(iv) at page 87. Sir, begging is not a great offence to be arrested without warrant. We can instead say,

> "He will be removed from that area." Sir, who is a beggar? he is seeking alms.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Okay, agreed ....*(Interruptions)*.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has agreed to it ....*(Interruptions)*.....

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, these are all the points I made, but I did not get replies from the hon. Minister ....*(Interruptions)*.....

SHRI N. JOTHI: Sir, first of all, nobody wants to be a beggar. After all, he is a soul ....*(Interruptions)*.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your point is well taken.

SHRI N. JOTHI: He is a soul born without a ....*(Interruptions)*.....

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have already acepted your point. Why are you going on arguing?

SHRI N. JOTHI: Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to the administration of cantonments with a view to impart greater democratisation, improvement of their financial base to make provisions for developmental activities, proper regulation, control and management of defence lands including extension of cantonment laws to such lands situated throughout the territory of India and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one amendment (No.4) by the hon. Minister.

CLAUSE–2

**Definitions**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, now, Sushmaji's thing comes. And, here, I can tell you one thing. Sir, just for one minute, I take your indulgence because I did not answer that point. I have taken note of your view. But, I thought as most of the amendments are related to the recommendations of the Standing Committee and others, but I thought that would have been better to reprint it. It would not have been very costly, but it would have given a lot of facility to the Members to read it. Henceforth, I will accept that. And now, my ordeal starts. *(Interruptions)*

Sir, I move:

4. That at page 3, *for* lines 40 and 41, the following be *substituted,* namely:—

"therein, or declared as such by the Chief Executive Officer and in case of a dispute, as decided by the District Magistrate;"

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 2, as amended, was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there is one amendment (No.5) by the hon. Minister.

CLAUSE–3

**Definition of cantonments**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

5. That at page 5, *for* lines 43 to 46, the following be *substituted,* namely:—

"(3) When any place is declared a cantonment under sub-section (1), the Central Government shall constitute a Board within a period of one year in accordance with the provisions of this Act:

Provided that the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, extend the said period of one year for a further period of six months at a time:

Provided further that the Central Government may, until a Board is constituted, by order make necessary provisions for the efficient administration of the cantonment."

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 3, as amended, was added to the bill.*

MR DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 4, there are two amendments (Nos. 6 and 7) by the hon. Minister.

CLAUSE–4

**Alteration of limites of cantonments**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

6. That at page 6, line 11, *for* the words "within six weeks" the words "within eight weeks" be *substituted.*

7. That at page 6, line 15, *for* the words "expiry of six weeks" the words "expiry of eight weeks" be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 4, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 5 was added to the Bill*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there are three amendments (nos. 8 to 10) by the hon. Minister.

CLAUSE–6

**Disposal of cantonment fund when area ceases to be a cantonment**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

8. That at page 6, line 25, in marginal headling, *after* the words "cantonment fund" the words "and cantonment development fund" be *inserted.*

9 That at page 6, line 27, *after the words* "cantonment fund" the words "or the cantonment development fund" be *inserted.*

10. That at page 6, line 32, *after* the words "cantonment fund" the words "or the cantonment development fund" be *inserted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 6, as amended, was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 7, there are three amendments (No.11 to 13) by the hon. Minister,

CLAUSE–7

**Disposal of cantonment fund when area ceases to be included in a cantonment**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

11. That at page 6, line 34, in marginal heading, *after* the words "cantonment fund" the words "and cantonment development fund" be *inserted.*

12. That at page 6, line 36, *after* the words "cantonment fund" the words "or the cantonment development fund" be *inserted.*

13. That at page 6, line 43, *after* the words "cantonment fund" the words "or the cantonment development fund" be *inserted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 7, as amended, was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 8, there is one amendment (No. 14) by the hon. Minister.

CLAUSE–8

**Application of funds and property transferred under sections 6 and 7**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

14. That at page 6, *for* line 46, the following be *substituted,* namely:—

"8. Any cantonment fund or a cantonment development fund or a portion thereof or other property of a"

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 8, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 9 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 10, there is one amendment (No. 15) by the hon. Minister.

CLAUSE–10

**Cantonment Board**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, move:

15. That at page 7, *for* lines 11 and 12, the following be *substituted,* namely:—

"(2) Every Board shall be deemed to be a municipality under article 243P(e) of the Constitution for the purposes of-

(a) receiving grants and allocations; or

(b) implementing the Central Government schemes of social welfare, public health, hygiene, safety, water supply, sanitation, urban renewal and education."

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 10, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 11 was added to the Bill.*

CLAUSE–12

**Constitution of Cantonment Boards**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause 12. There are three amendments (Nos. 96 to 98) by Smt. Sushma Swaraj.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I beg to move:

96. That at page 7, *line* 40, *for* the words "eight members" the words "nine Members" be *substituted.*

97. That at page 8, line 13, *for* the words "seven members" the words "eight members" be *substituted.*

98. That at page 8, line 44, *for the words* "but without a right to vote" the words "with a right to vote" be *substituted.*

सर, मैं तीनों अमेंडमेंट मूव करती हूं। मैं रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उन्होंने जवाब देते हुए यह कहा कि पैरिटि लाने के लिए हमने 7 से 8 और 6 से 7 किया। मेरा फिर से कहना यह है कि जब हम ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या पदेन और मनोनीत सदस्यों से चाहे एक ज्यादा हो, ज्यादा होनी चाहिए या तो हम यह नहीं कहें कि हम लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं। फिर हम कहें कि हम अधिकारियों के माध्यम से चलाना चाहते हैं। दूसरा, मैंने कहा था कि ईवन और ओड का मामला। जब सारे फैसले वोट से होने हैं, तो एक नम्बर ज्यादा होना चाहिए। अब आपके नम्बर 8 और 8 मिलकर 16 हो रहे हैं या 7 और 7 मिलकर 14 हो रहे हैं। इसलिए मैं तीनों अमेंडमेंट प्रेस करती हूं, क्योंकि ये साउंड अमेंडमेंट हैं बहुत लोगों ने कहा है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या केटेगरी वन में 9 हो जाये मतलब क्लास वन कंटोनमेंट्स में और केटेगरी टू Cantonments में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 7 की जगह पर 8 हो जाये।

सर, मैं संशोधन प्रस्तुत करती हूं।

*The questions were proposed.*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I have already replied that this is not possible and in many of the Boards there are even number of members. So, it is not that insurmountable problems. Let us have it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I now put the amendments (Nos. 96 to 98) to vote.

*Amendments (Nos. 96 to 98) were negative.*

*Clause 12* was added to the Bill.

*Clause 13 was added to the Bill.*

CLAUSE–14

**Term of office of members**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 14. There is two amendments (Nos. 16 & 17) by the Minister

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move that:

16. That at page 9, for lines 29 to 32, the following be substituted, nemely:—

"14. (1) Save as otherwise provided in this section, the term of office of a member of a Board shall be five years and shall commence—

(a) in case of an elected member, from the date of notification of his election under sub-section (8) of section 12, or from the date on which the vacancy has occurred to which he is elected, whichever is later; and

(b) in case of a nominated member, from the date of nomination under clauses (b) and (f) of sub-section (3), clauses (b) and (f) of sub-section (4) and clauses (b) and (f) of sub-section (5) of section 12, or the date of vacancy under clause (b) of sub-section (1) of section 18, whichever is later, and the member so nominated shall be able to take part in the proceedings of the Board:"

17. That at page 9, *for* lines 46 and 47, the following be *substituted* namely--"continue in office until the election of his successor is notified under sub-section (8) of section 12 or the nomination of his successor, as the case may be."

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 14, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 15 was added to the Bill.*

CLAUSE–16

**Vacancies in special cases**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 16. There are four amendments (No. 18 to 21).

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move that:

18. That at page 10, *for* lines 10 tc 16, following be *substituted* namely:—

"16. (1) If for any cause at an election no member is elected, or if the elected member is unwilling to serve in the Board, fresh election shall be held to fill up such vacancy."

19. That at page 10, lines 25 to 28, be *deleted.*

20. That at page 10, line 29 *for* the bracket and letter "(c)", the bracket and letter "(b)", be *substituted.*

21. That at page 10, *for* lines 41 to 43, the following be substituted namely:—

"(5) The term of office of a member nominated under this section shall expire at the time at which it would have expired if he had been elected at the casual election"

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 16, as amended, was added to the Bill.*

CLAUSE–17

**Oath of affirmation**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 17. There are two amendments (Nos. 22 and 23) by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

22. That at page 10, line 44, the bracket and figure "(1)" be *deleted.*

23. That at page 11, lines 1 to 5 be *deleted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

CLAUSE 17, *as amended, was added to the Bill.*

CLAUSE–18

**Resignation**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 18. There is one amendment (No. 24) by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move that:

24. That at page 11, line 7, *for* the words"forward it for orders" the words "forward it for acceptance and notification" be *substituted.*

*The question was put and motion was adopted.*

*Clause 18, as amended, was added to the Bill.*

CLAUSE–1

**President and Vice-President**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 19. There are three amendments (Nos. 25 and 26) by the Minister and (No. 99) by Smt. Sushma Swaraj.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I move:

99. That at page 11, *for* lines 20-21, the words "The President of the Board shall be elected from amongst the elected members of the Board" be *substituted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put to vote the amendment of Smt. Sushma Swaraj.

*Amendment No. 99 was negatived.*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move that:

25. That at page 11, line 29, *after* the words "In every Board", the words "except in case of a Board falling under Category IV Cantonment" be *inserted.*

26. That at page 11, after line 31, the following be inserted, namely:— "(4) In case of a Board falling under Category IV Cantonment, the Vice-President shall be elected by draw of lot under the supervision of the President of the Board in such manner as he may decide."

*The questions were put and motions were adopted.*

*Clause 19, as amended, was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 20. There is one amendment (No. 27) by the Minister.

CLAUSE–20

**Term of office of Vice-President**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

27. That at page 11, *for* line 42, the following be *substituted,* namely—"if a resolution to this effect is passed by the Board and the other elected member shall become the Vice -President."

*The questions were put and motions were adopted.*

*Clause 20, as amended, was added to the Bill.*

***Clauses 21 to 25 were added to the Bill.***

CLAUSE–26

**Special Power of the Chief Executive Officer**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 26 of the Bill. There is one amendment (No. 28) by the hon. Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I beg to move:

That at page 13, *for* line 16, the following be *substituted*, namely:—

"State with the approval of the Central Government"

*The question was put and motion was adopted.*

*Clause 26, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses - 27 and 28 were added to the Bill.*

CLAUSE–29

**Qualification for being a member of the Board**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now take up clause 29 of the Bill. There is one amendment (No.29) by the hon. Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

That at page 14, line 34, *for* the words "as a legal practitioner by order of any competent" the words this prefession or callings by order of any competent" be *substituted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 29, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses - 30 to 38 were added to the Bill.*

CLAUSE–39

**Meetings**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 39 of the Bill. There is one amendment (No.30) by the hon. Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

That at page 19, line 33, *after* the words 'in like manners the words "but not more than twice except in case of a public emergency" be *inserted.*

*The question was put and motion was adopted.*

*Clause 39, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 40 to 42 were added to the Bill.*

CLAUSE-43

**Minutes**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 43 of the Bill. There are two amendments (Nos. 31 & 32) by the hon. Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

That at page 20, *for* line 11, the following be *substituted,* namely:—

"Cantonment and its authenticated copies may be made available to him on request, at a nominal cost to be decided by the Board."

That at page 20, line 13 *after* the words " or information to" the words "every Member of the Board,"be *inserted.*

*The questions were put and motions were adopted.*

*Clause 43, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 45 to 46 were added to the Bill.*

CLAUSE–47

**Committees for civil areas**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 47 of the Bill. There are two amendments (Nos. 33 and 34) by the hon Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

That at page 20, *for* lines 41 to 43, the following be *substituted,* namely:—

"137, section 143, section 147, section 149 and section 262 shall be exercised or discharged in respect of a civil area by the civil area committee"

That at page 20, lines 45, the word and figure" section 140" be *deleted.*

*The questions were put and motions were adopted.*

*Clause 47 as amended, was added to the Bill.*

*Clause 48 to 61 were added to the Bill.*

CLAUSE–62

**Duties of Board**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 62. There are three amendments (Nos. 35, 36 and 37) by the hon. Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

That at page 25, line 26, *for* the words "pure and wholesome"the word "potable" be *substituted.*

That at page 26, *after* line 2, the following be *inserted*, namely"

"(xxiii) celebrating Independence Day and Republic Day and incurring expenditure thereon;"

That at page 26, line 3, for the bracket and roman numeral"(xxiii)" the bracket and roman numeral "(xxiv)" be substituted.

*The questions were put and motions were adopted.*

*Clause 62, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 63 was added to the Bill.*

*Clause: 64 - Discretionary functions of Board*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 64. There are three amendments ( Nos. 38, 39 and 40) by the hon. Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

That at page 26, *for* lines 41 and 42, the following be *substituted,* namely:—

"(xvii) conservation and maintenance of ancient and historical monuments, archaeological sites and remains or place of public importance in the cantonment;"

That at page 27, after line 36, the following be inserted, namely:—

"Explanation "For the purposes of clause (xvii)"

(a) "conservation" means the supervision, management and maintenance of a place to retain its historical, architectural, aesthetic or cultural significance or of environment and includes the protection, improvement, preservation, restoration, reconstruction and adoption or a combination of more than one of these activities, and the use of such place in a way that ensures the social as well as economic benefits;

(b) "ancient and historical monuments, archaeological sites and remains or place of public importances include buildings, artefacts, structures, areas, or precincts of historical or aesthetical or educational or scientific or cultural or environmental significance, and those natural features of environmental significance or scenic beauty, as may be declared by the Board."

That at page 27, *for* line 40, the following be *substituted*, namely:—

"cantonment fund or the cantonment development fund"

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 64, as amended, was added to the Bill.*

CLAUSE–66

**General Power of Taxation**

**MR. DEPUTY CHAIRMAN:** We shall now take up clause 66. There is one amendment (No. 100) by Shrimati Sushma Swaraj:

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

100. That at page 28, clause 66 be *deleted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the amendment (No. 100) moved by Shrimati Sushma Swaraj to vote.

Amendment (No. 100) was negatived

Clause 66 was added to the Bill.

CLAUSE-67

**Charging of fees**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up Clause 67. There is one amendment (101) by Shrimati Sushman Swaraj.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I beg to move:

(101) That at page 28, clause 67 be *deleted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put to vote the amendment of Smt. Sushma Swaraj.

*Amendment No.(101) was negatived.*

*Clause 67 was added to the Bill.*

CLAUSE-68

**Norms of property tax**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause 68. There is one amendment (No. 102) by Shrimati Sushma Swaraj.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I beg to move:

(102) That at page 29, lines 2-3, the words " and shall consist of not less than ten and not more than thirty per cent of the annual rateable value of lands and buildings" be *deleted.*

*Amendment No.(102) was negatived.*

*Clause 68 was added to the Bill.*

*Clauses 69 to 76 were added to the Bill.*

CLAUSE-77

**Authentication of assessment list**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause 77. There is one amendment (No.41) by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

41. That at page 31, lines 23 and 24, *for* the words "or Principal Director or Director, Command" the words "the Command or the Principal Director" be *substituted.*

*The question was put and motion was adopted.*

*Clause 77, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 78 to 91 were added to the Bill.*

CLAUSE-92

**Lease of octroi, terminal tax or toll**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause 92. There is one amendment (No. 42).

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move that:

42. That at page 35, line 9, the words "President Cantonment" be *deleted.*

*The questions was put and motion was adopted.*

*Clause 92, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses: 93 to 95 were added to the Bill.*

CLAUSE-96

**Conditions of right to appeal**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause 96. There is one amendment (No. 43).

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

43. That at page 36, line 17, *for* the words "appeal is determined", the words "appeal is decided" by *substituted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 96, as amended, was added to the Bill.*

CLAUSE-97

**Finality of appellate orders**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause 97. There is one amendment (No. 103) by Shrimati Sushma Swaraj.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I beg to move:

(103) That at page 36, clause 97 be *deleted.*

सर, मैं संशोधन प्रस्तुत करते हुए कुछ बोलना चाहती हूं और आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा क्योंकि आप भी लगातार बोल रहे हैं। यह सुविधाजनक होगा। ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति:** इसलिए बोलना चाहती हैं।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सर, धारा-97 पर बोलते हुए, माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इस पर स्टैंडिंग कमेटी की कोई सिफारिश नहीं है। मैं जानती हूं कि इस पर स्टैंडिंग कमेटी की कोई सिफारिश नहीं है और मैंने प्रारम्भ में ही यह कहा था कि शायद ज्यादातर अमेंडमेंट्स स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों से लिए हैं, लेकिन कुछ उनसे अलग भी लिए हैं, जैसे धारा-12,

उपधारा-9 का अमेंडमेंट्स है, स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश नहीं हुई है। धारा-19, उपधारा-1 एक का अमेंडमेंट्स, स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश नहीं हुई है। लेकिन धारा-97 में स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश क्यों नहीं है, यह मैं आपको बताना चाहती हूं। उपसभापति जी, धारा-97 finality of orders के बारे में है, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आर्डर फाइनल होगा, सुपररियर कोर्ट्स में आप अपील नहीं कर सकते, यानी न आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और न ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, केवल डिस्ट्रिक्स कोर्ट का आर्डर फाइनल होगा। इस धारा-97 पर स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश इसलिए नहीं है क्योंकि 97 का सीधा संबंध 93 से है। आप धारा-93 पढ़िए, इसमें जहां पर अपील का चैप्टर शुरू होता है, वहां पर कहा गया है:

> "An appeal against the assessment or levy of, or against the refusal to refund, any tax under this Act shall lie to the District Court."

धारा-93 यह कहती है कि डिस्ट्रिक्स कोर्ट पहला कोर्ट होगा, जहां अपील होगी। यानी उससे पहले लोअर कोर्ट्स में अपील नहीं होगी। धारा-97 यह कहती है कि यह आखिरी कोर्ट होगा। जब हम 93 और 97 को इकट्ठा पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह बिल कह रहा है कि पहली और अंतिम अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होगी, तो स्टैंडिंग कमेटी ने 93 पर अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उन्होंने 93 में यहा कहा था:

> "The Committee feels that administrative mechanism should be put in place to hear the appeal against the assessment or levy of or against the refusal to refund any tax under this act, so that the cantonment inhabiants should not have to take recourse to district courts which is costlier and time-consuming affair;"

तो स्टैंडिंग कमेटी को यह लगा कि 93 की अमेंडमेंट सरकार मान लेगी, तो फिर 97 की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए उन्होंने 97 पर किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपील का पहला कोर्ट है और आखिरी कोर्ट है, चूंकि उन्होंने 93 की रिकमेंडेशन नहीं मानी, इसलिए मैंने 97 को डिलीट करने का संशोधन दिया है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का बताना चाहती हूं कि अगर आप स्टैंडिंग कमेटी द्वारा धारा 93 में की गई recommendations मान लेते, तो मैं भी धारा 97 का अमेंडमेंट लेकर नहीं आती, लेकिन चूंकि स्टैंडिंग कमेटी ने धारा 93 में recommendations दी थीं और यह कहा था कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले, अपील सुनने का एक administrative mechanism बनाइए। अगर आप मुझे यह आश्वासन देते हैं कि आप administrative mechanism बनाएंगे, तो मैं अपना संशोधन press नहीं करूंगी, लेकिन आप कहते हैं कि आप कोई administrative mechanism नहीं बनाएंगे, तो मैं अपना संशोधन press करूंगी।

*The question was proposed*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I will look into it. That is a good suggestion. But, I just cannot make the commitment and change it. It is relating to administrative mechanism. It cannot be provided in the Act.

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** फिर मैं press करूंगी।

**श्री उपसभापति:** वे assurance दे रहे हैं कि I will look into it. वे बोल रहे हैं कि it is a good suggestion. एक तो withdraw करो।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सर, मेरा संशोधन तो वैसे भी नैगेटिव होना है, कौन सा उसका पार्ट होना है, तो कम से कम मै। press करूं।

**श्री प्रणब मुखर्जी:** ठीक है, आप press कीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I will put the motion to vote.

*Amendment No. 103 was negatived.*

*Clause 97 was added to the Bill.*

*Clause 98 was added to the Bill.*

CLAUSE-99

**Public notice for taxes due**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments Nos. 44 and 45 by the hon. Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 44) That at page 36, line 28, *for* the words "public notice to be issued", the words "separate bill and public notice to be issued as well as published in a local news paper" be *substituted.*

(No. 45) That at page 36, *for* lines 31 to 33, the following be *substituted,* namely—

"(3) Any non receipt of a bill by a person shall not be a cause for non-payment of the tax notified under sub-section (1)".

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 99, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 100 to 103 were added to the Bill.*

CLAUSE-104

**Disposal of distrained property**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments nos. 46 and 47 by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 46) That at page 38, lines 5 to 10, be *deleted.*

(No. 47) That at page 38, line 11, *for* the bracket and figure "(4), the bracket and figure "(3)" be *substituted.*

*The question were put and the motions were adopted.*

*Clause 104, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 105 was added to the Bill.*

CLAUSE-106

**Recovery from a person about to leave cantonment**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are to amendments nos. 48 and 49 by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 48) That at page 38, line 44, for the existing marginal heading, the following marginal heading be *substituted,* namely—

"Recovery from a person about to leave cantonment and refund of surplus sale proceeds, if any"

(No. 49) That at page 39, after line 5, the following be *inserted,* namely—

"(3) The surplus of the sale proceeds arising out of section 104, section 105 and this section, if any, shall immediately after the sale of the property, be credited to the cantonment fund, and the notice of such credit shall immediately be given to the person whose property has been sold, or to his legal representative and, if such money is claimed, within a period of one year from the date of notice, a refund thereof shall be made to the said person or his representative.

(4) Any surplus of the sale proceeds not claimed within one year as aforesaid shall be the property of the Board."

*The questions were put and the motions were adopted*

*Clause 106, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 107 was added to the Bill.*

CLAUSE-108

**Every Board to be a Municipality for certain purposes**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment no. 50 by Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

That at page 39, for lines 12 to 16, the following be substituted, namely—

"Board to be a 108. A Board shall be deemed to be a municipal Municipality for committee for the purposes of taxation as per the taxation Municipal Taxation Act, 1881."

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 108, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 109 to 113 were added to the Bill.*

CLAUSE-114

**Composition**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment no. 51 by Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I move:

(No. 51) That at page 40, line 7 *for* the words "Chief Executive Officer" the word, "Board" be *substituted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 114, as amended, was added to the Bill.*

CLAUSE-115

**Irrecoverable debts**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments nos. 52 and 53 by Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 52) That at page 40, line 11, *for* the words "Chief Executive Officer", the word, "Board" be *substituted.*

(No. 53) That at page 40, line 15, *for* the words "President of

Cantonment board", the words "General Officer Commanding-in-Chief, the Command" be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 115, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 116 was added to the Bill.*

CLAUSE-117

**Immaterial error not to affect liability**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment no. 54 by Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 54) That at page 40, for lines 38 and 39, the following be substituted, namely—

"shall be entitled to recover such compensation for the same, as the Board may decide."

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 117-as amended, was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 118, there is one amendment (No. 55) by the hon. Minister.

CLAUSE-118

**Distraint not to be invalid by reason of immaterial defect**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

55. That at page 40, *for* lines 46 and 47, the following be *substituted,* namely—

"be entitled to recover such compensation for the same, as the Board may decide"

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 118, as amended, was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 119, there are four amendmetns (Nos. 56 to 59) by the hon. Minister.

CLAUSE-119

**Cantonment fund**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

56. That at page 41, line 4, *for* the existing marginal heading, the following marginal heading be *substituted,* namely—

"Cantonment fund and Cantonment development fund."

57. That at page 41, line 9, be *deleted.*

58. That at page 41, line 10, *before* the words "There shall" the bracket and figure '(2)' be *inserted.*

59. That at page 41, line 15, *for* the words "received by" the words "received from" be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 119, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 120 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 121, there is one amendment (No. 60) by the hon. Minister.

CLAUSE-121

**Power of Board to borrow money**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

60. That at page 41, line 44, *for* the word "Board" the words "Board, on mutually agreeable terms," be *substituted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 121, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 122 to 127 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 128, there are two amendments (Nos. 61 and 62) by the hon. Minister.

CLAUSE-128

**Execution of contract**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

61. That at page 43, lien 22, *for* the figure "128" the figures and bracket "128.(1) be *substituted.*

62. That at page 43, *after* line 26, the following be *inserted,* namely—

"(2) Where the Chief Executive Officer executes a contact on behalf of the Board sanctioned under sub-section (2) of section 127, he shall submit a report, on the execution of the contract, to the Board at its next meeting."

*The Question were put and the motions were adopted.*

*Clause 128, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 129 to 131 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 132, there is one amendment (No. 63) by the hon. Minister.

CLAUSE -132

**Public latrines, urinals and conservancy establishments**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

63. That at page 44, *for* line 22, the following be *subsituted,* namely—

"constructed as to provide separate compartments for each sex and the compartments so constructed shall be made accessible to and barrier free for the persons with disabilities".

*The Question was put and the motions were adopted.*

*Clause 132, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 133 to 165 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 166, there is one amendment (No. 64) by the hon. Minister.

CLAUSE - 166

**Penalty for failure to report**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

64. That at page 52, *for* line 13, the following the *substituted,* namely—

"extend to one thousand rupees."

*The Question was put and the motions were adopted.*

*Clause 166, as- amended, was added to the Bill.*

*Clauses 167 to 184 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 185, there is one amendment (No. 65) by the hon. Minister.

CLAUSE-185

**Conditions of service of safaikaramcharis and other**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

65. That at page 55 *for* line 50, the following be *substituted,* namely—

"may extend to one month; and the conditions of service specified herein shall, invariably be mentioned in the appointment letters of the persons employed to said services."

*The Question was put and the motion was adopted.*

*Clause 185, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 186 to 209 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 210, there one amendment (No. 66) by the hon. Minister.

CLAUSE-210

**Construction and control of drains and sewage collection and disposal works**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

66. That at page 62, *after* line 28, the following be *inserted,* namely

"(4) The Board shall ensure that the sewage effluents are treated in accordance with the norms laid down under the relevant laws relating to pollution before it is dispersed into a river, stream, lake or open land."

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 210, as amended, as added to the Bill.*

*Clauses 211 to 232 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 233, there are two amendments (Nos. 67 and 68) by the hon. Minister.

CLAUSE-233

**Preparation of land use plan**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

67. That at page 69, *for* lines 44 to 46, the following be *substituted,* namely--

"233. (1) On the commencement of this Act, the Chief Executive Officer shall with the approval of the Board, cause to be prepared a spatial plan for land use to be followed in the cantonment which shall include--"

68. That at page 70, *after* line 5, the following be *inserted,* namely—

"(2) The Board shall give publicity to the land use plan prepared under sub-section (1), by publishing a gist of the plan in a local newspaper."

*The question were put and the motions were adopted.*

Clause 233, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 234, there is one amendment (No. 69) by the hon. Minister.

CLAUSE-234

**Sanction of building**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir I move:

69. That at page 70, *after* line 12, the following be *inserted,* namely—

"Provided that if an erected or re-erected building is meant for public purposes, then it shall be made accessible to and barrier free for the persons with disabilities."

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 234, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 235 to 238 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 239, there is one amendment (70) by the hon. Minister:

CLAUSE-239

**Order of stoppage of building or works in certain cases and disposal of things removed**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

70. That at page 72, *for* lines 48 and 49, the following be *substituted,* namely—

"the Chief Executive Officer by a public auction or in such other manner as he thinks fit:

Provided that such things shall only be disposed of by the Chief Executive Officer on the expiry of fifteen days in case of non-perishable things and twenty-four hours in case of perishable things from the date and time of seizure."

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 239, as amended, was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 240 there are three amendments (No. 71, 72 and 73) by the hon. Minister.

CLAUSE-240

**Power to sanction general scheme for prevention of overcrowding, etc**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

71. That at page 73, line 6, *for* the words The Central Government", the words "The General Officer Commanding-in-Chief, the Command in consultation with the Principal Director" be *substituted.*

72. That at page 73, line 11, *for* the words "The Central Government", the words "The General Officer Commanding-in-Chief, the Command" be *substituted.*

73. That at page 73, line 17, the following be *substituted,* namely—

"along with his recommendations to the Principal Director"

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 240, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 241 to 243 were added to the Bill.*

CLAUSE-244

**Restrictions on use of buildings**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 244, there is one amendment (No. 104) by Shrimati Sushma Swaraj.

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** उपसभापति महोदय, मैं प्रस्तुत करती हूं कि:

104. That at page 74, *after* line 5, the following be *inserted,* namely:—

"Provided that the fine under this sub-section on contravention shall be as per the provisions of bye-laws of adjoining municipality."

सर, धारा 244 लेंड यूज के उल्लंघन पर पाबंदियां लगाने की धारा है, लेकिन 244 की उपधारा-2 जिस में मैंने संशोधन दिया है, वह कितना कड़ा प्रावधान करती है, यह आप देखिए। "Any person who contravenes the provision of sub-section (1) shall on conviction be punishable with a fine which may extend to Rs. one lakh, and in case of continuing contravention, with an additional fine of Rs. 10,000/- for every day during which the contravention continues after the date it comes to the notice." यानी एक लाख रुपया और उस के बाद 10 हजार रुपए प्रतिदिन-यह बात जब स्टेंडिंग कमेटी के सामने रखी गयी तो स्टेंडिंग कमेटी को लगा कि यह बहुत ही कठोर प्रावधान है। म्युनिसपल कमेटीज में इस तरह के चेंजेज होते हैं, कैंटोनमेंट तो लेंड यूज बहुत ही मुश्किल से चेंज करने देते हैं। सर, मैं यहां स्टेंडिंग कमेटी की रिकमंडेशन आप को पढ़कर सुनाती हूं। आप देखें स्टेंडिंग कमेटी ने क्या कहा था।

"The Committee understands that fine imposed under the clause is on the higher side. But the Committee feels that to maintain the very nature of the Cantonment Board, nobody should be allowed to change the character of the property on his own as this goes against the very spirit of the provisions of the clause". पर उस का समाधान क्या बताया, Therefore, the Committee recommends that the provisions under this caluse should be as per the bye-laws in adjoining municipalities. और दूसरे कहा "The Committee further desires that before imposing any fine under this clause, individual concerned should be given due notice and his reply thereto should considered by the Board. अब ये इतनी अच्छी रिकमंडेशंस थीं, पर क्या सरकार में संवेदनशीलता का बिल्कुल ही अभाव है कि ऐसे-ऐसे प्रावधान यहां किए जा रहे हैं, लेकिन कमेटी रिकमंड कर रही है, अनुशंसाएं कर रही है, और आप कह रहे हैं कि हम ने 92 में से 42 ले लिए हैं। आप ने ये 42 या तो innocuous ले लिए हैं यहा डिफेंस मैनेजमेंट, डिफेंस लेंड का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। इन्हें ले लिया, लेकिन जो जनता को राहत देने वाली सिफारिशें थीं, जहां काफी एसोसिएशंस व ऑर्गनाइजेशंस आए और उनको सुनने के बाद उन्होंने ये सिफारिशें कीं, उन्हें नहीं लिया। मैं रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप ने नागरिकों को राहत देने वाली

कौनसी सिफारिश मंजूर की? यह सिफारिश थी कि एक तो उस को नोटीस दो, उस को राइट टू रिप्लायी दो, सुनवाई करो और दूसरी कहती है कि अपनी तरफ से तय करने के बजाय आप एक लाख रुपए या दस हजार रुपए प्रतिदिन आप जो भी एडजॉइनिंग म्युसिपैलिटी है व उस में जो बायलॉज हैं, वे ले लो।

मैं चाहूंगी कि कम-से-कम इस को तो रक्षा मंत्री जी स्वीकार करें।

*The question was proposed.*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, as the question of putting or levying fine will come after the competent court finds and confirms the conviction, that is, after it finds the person guilty and after the confirmation of the conviction. Therefore, it is not correct to say that he is not being given a chance. He is given a change in the competent court.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put amendment no. 104 moved by Shrimati Sushma Swaraj to vote.

*Amendment (No. 104) was negatived.*

*Clause 244 was added to the Bill.*

*Clauses 245—248 were added to the Bill.*

*Clause 249: Power to seal unauthorised constructions.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 249. There is one amendment no. 105 by Shrimati Sushma Swaraj.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I move.

That at page 75, *after* line 23, the following proviso be *inserted*, namely:—

> "Provided that the power to seal unauthorized construction and to impose penalty shall be available to the Cantonment Board only and the affected party shall have the right to file an appeal against the decision of the Board.

सर, यह संशोधन प्रस्तुत करते हुए मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जरा आप वह देखें, जो प्रारंभ में मैंने कहा था कि CEO को असीमित शक्तियाँ दे दी गई हैं, unilimted powers. यहाँ बिल्डिंग को सील करने की, पेनल्टी लगाने की, सारी की सारी शक्तियाँ CEO को दे दी गई हैं। वे इलेक्टेड मैम्बर्स क्या करेंगे? आप इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि हमने 7 से 8 कर दिए। कर

तो दिए, आपने वहाँ पर एम०एल०ए०-एम०पी० भी बना दिए, मैम्बर्स स्पेशल इनवाइटीज़ लेकिन वे सब दर्शनीय ही रहेंगे। ये जो असीमित शक्तियाँ दी गईं हैं, इस पर भी मैं आपको सुनाती हूँ। आप इस पर स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन देखिए। The Committee notes that there is a provision for imprisonment of any person who contravenes the provisions contained in sub-clause 3 of this clause may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees or both. The power to seal unauthorized construction and to impose penalty should be available to Cantonment Board only. पूरे-का-पूरा बोर्ड जब बैठे, तो कहता है कि it should be available to Cantonment Board only, and there should be a provision for preferring an appeal against the decision of the Board. The Committee desires that there should be an appellate authority specified in this clause itself. तो मैं बार-बार वही कह रही हूँ कि सारी-की-सारी सिफारिशें जो जनता के हित में हैं, इसको थोड़ा संवेदनशील बनाने के लिए लाई थीं, उसे रक्षा मंत्री जी मान ही नहीं रहे हैं। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। मैं संशोधन प्रस्तुत करती हूँ।

*The question was proposed.*

**श्री प्रणब मुखर्जी:** आप प्रस्तुत कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। The problem is that the violation is of a sanction given under the by-laws approved by the Central Government. Powers for fine and imprisonment are with the courts, and the issues of notice and appellate authority are taken care of by the systems of the court itself. Therefore, he is getting the opportunity there. And why the authority is given instead of the Board? The very first point to be kept in mind is that overall responsibility of maintaining discipline should be vested not on the Board, in that case, it will have to be given a total Municipal Board authority. It will be with the Station Commander or the Chief Executive there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the amendment no. 105 moved by Shrimati Sushma Swaraj to vote.

*Amendment no. 105 was negatived.*

*Clause 249 was added to the Bill.*

*Clauses 250—264 were added to the Bill.*

CLAUSE-265

**Public markets and slaughter houses**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 265. There is one amendment no. 74 by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move: That at page 79, line 32 *for* the words "either within or without the cantonment", the words "on the land under its control" be *substituted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 265, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 266 was added to the Bill.*

CLAUSE-267

**Power to transfer by public auction, etc.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause, 267. There are two amendments nos. 75 and 76 by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move.

75. That at page 80, *for* lines 12 and 13 the following be *substituted,* namely:—

"sanction of the General Officer Commnading in Chief, the Command or in his absence, the Principal Director".

101. That at page 80 *for* lines 23 and 24 the following be *substituted,* namely:—

"approved by the General Officer Commanding-in-Chief, the Command or in his absence, the Principal Director".

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 267, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 268—301 were added to the Bill.*

CLAUSE-302

**Removal and exclusion from cantonment of disorderly persons**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 302. There is one amendment no. 77 by Shri Pranab Mukherjee.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

That at page 92, *for* lines 21 to 24 the following be *substituted,* namely:—

6.00 P.M.

"maintenance of good order in the cantonment that such person is required to be removed therefrom and be prohibited from re-entering the cantonment, the Magistrate shall inform the matter to the Officer Commanding the Station and, the Officer Commanding the Station shall cause to be served on such person an order in"

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 302, as amended was added to the Bill.*

*Clauses 303-304 were added to the Bill.*

CLAUSE-305

**Management of defence lands**

**MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 305. There is one amendment no. 78 by the Minister.**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

That at page 93, clause 305 be *deleted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 305, as amended, was added to the Bill.*

**MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sir, now, we shall take up Clause 306. There is one amendment (No. 79) by the hon. Minister.**

***Clause 306— Application of Act to Defence Lands.***

**SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:**

(79) That at page 93-94, Clause 306 be *deleted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 306, as amended, was added to the Bill.*

**MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, in Clause 307, there is one amendment (No. 80) by the hon. Minister.**

CLAUSE-307

**Vesting of land in a board**

**MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sir, I move:**

**(80) That at page 94, Clasue 307 be *deleted.***

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 307, as amended, was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, in Clause 308, there is one amendment (No. 81) by the hon. Minister.

CLAUSE-308

**Role of Defence Estates Officer and Local Military Authorities**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(81) That at page 94, Clause 308 be *deleted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 308, as amended, was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause 309. There is one amendment (No. 82) by the hon. Minister.

CLAUSE-309

**Land Audit**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, move:

(82) That at page 94, Clause 309 be *deleted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 309, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 310 to 326 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause 327. There is one amendment (No. 83) by the hon. Minster.

CLAUSE-327

**Liability of occupier to pay in default of owner**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(83) That at page 98, line 17, *after* the words" he is the owner" the words "and he fails to comply with the notice so given" be *inserted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 327, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 328 to 343 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause 344. There is one amendment by Shrimati Sushma Swaraj.

CLAUSE-344

**Notice to be given of suits**

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I move: (106) That at page 102, *after* line 13, the following proviso be *inserted,* namely:—

"Provided that general provisions as prescribed under civil law shall be made applicable in such case."

सर, इस बिल में मेरे द्वारा दिया हुआ यह अंतिम संशोधन है। यह धारा 344 एक अद्भुत धारा है। आपको मालूम है कि हमारे देश में दीवानी मामलों के लिए सिविल प्रोसीजर कोड है, फौजदारी मामलों के लिए क्रिमिलन प्रोसीजर कोड है, लेकिन अगर हम कोई अपना अलग-अलग प्रोसीजर बना लेगा, तो क्या स्थिति बनेगी? अब यह धारा इतना अलग प्रोसीजर बना रहीं है, मैं इसे पढ़ती हूँ–No suit shall be instituted against any Board or against any member of a Board, or against any officer or employee of a Board, in respect of any act done, or purporting to have been done, in pursuance of this Act or of any rule or bye-law made thereunder, until the expiration of two months after notice in writing has been left at the office of the Board, and, in the case of such member, office or employee, unless notice in writing has also been delivered to him or left at his office or place of abode, and unless such notice states explicitly the cause of action, the nature of the relief sought, the amount of compensation claimed, and the name and place of abode of the intending plaintiff, and unless the plaint contains a statement that such notice has been so delivered or left."

मतलब, हर एक्ट और हर संस्था अपने लिए अलग प्रावधान करेगी कि कैसे नोटिस दिए जाएंगे। सर, आपको मालूम है कि सिविल प्रोसीजर कोड में तय है कि कैसे नोटिस दिया जाएगा, कैसे plaint बनेगी, कैसे सम्मन जारी होंगे, लेकिन अब यह धारा अपने लिए,कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए अलग ही प्रोसीजर बना रही है और इसीलिए स्टेंडिंग कमेटी के सामने जब यह मसला आया, तो उन्होंने सीधे इसमें यह रिकमंड किया "The Committee recommends that general provisions as prescribed under civil law should be made applicable to this case also." अब रक्षा मंत्री जी यह भी स्वीकार नहीं करते, तो ठीक है। मैं तो अपना संशोधन प्रस्तुत करूंगी।

*The question was proposed.*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It is not possible to accept it, as I mentioned to you, because these are not ordinary matters. Therefore, it is not acceptable, and it was originally there in the old Act of 1924 itself. We are retaining it. Till now, there has not been any problem. And everybody is aware, with regard to properties, and especially land, how much litigaiton is involved and how much time-consuming it is. Therefore, this kind of a provision must be there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the amendment no. 344 moved by Shrimati Sushma Swaraj to vote.

*Amendment no. 344 was negatived.*

*Clause 344 was added to the Bill.*

CLAUSE-345

**Appeals from Executive Orders**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are three amendments, (Nos. 84 to 86), by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 84) That at page 102, *after* line 20, the following be *inserted,* namely:

> "(2) the Central Government may, for the purposes of expeditious disposal of the pending appeals, by notification in the Official Gazette, amend Schedule V so as to designate additional appellate authority in the fourth column of the said Schedule."

(No. 85) That at page 102, line 21, *for* the bracket and figure "(2)" the bracket and figure "(3)" be *substituted.*

(No. 86) that at page 102, line 23, *for* the bracket and figure "(3)" the bracket and figure "(4)" be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 345, as amended, we added to the Bill.*

*Clauses 346 to 351 were added to the Bill.*

CLAUSE-352

**Supplemental provisions respecting rules**

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: There are two amendments, (Nos. 87 and 88), by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 87) That at page 103, lines 34-35, the words "or defence estates" occurring at two places be *deleted.*

(No. 88) That at page 103, line 38 for the figure "2003" the figure "2006" be *substituted.*

*The qeustions were put and the motions were adopted.*

*Clause 352, as amended, was added to the Bill.*

CLAUSE-353

**Power to make bye- laws**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The are three amendments, (Nos. 89 to 91), by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 89) That at page 106, line 41, the word "and" be *deleted.*

(No. 90) That at page 106, *after* line 41 the following be *inserted,* namely:—

" (43) the conservation and maintenance of ancient and historical monuments, archaeological sites and remains or place of public importance in the cantonment; and"

(No. 91) That at page 106, line 42, *for* the bracket and figure (43), the bracket and figure (44) be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 353, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 354 to 365 were added to the Bill.*

**Schedule-I: Notice of Demand**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment, (No. 92), to Schedule-I by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 92) That at page 110, line 12, *for* the words "paid to the a Board" the words "paid to the Board" be *substituted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Schedule I, as amended , was added to the Bill.*

**SCHEDULE-II: Form of Demand**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments, (Nos. 93 and 94), to schedule II by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 93) That at page 111, line 3, *for* the words "FORM OF DEMAND" the words "FORM OF WARRANT" be *substituted.*

(No. 94) That at page 111, line 12 *for* the figure "2003" the figure "2006" be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Schedule II, as amended , was added to the Bill.*

*Schedules III and IV were added to the Bill.*

*Schedule V: Appeals from Executive Orders*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment, (No. 95) to Schedule V by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 95) That at pages 114-115 *for* "Schedule V", the following be substituted, namely:—

## SCHEDULE-V

## APPEALS FROM EXECUTIVE ORDERS

(*See* section 345)

| Sl. No. | Section | Executive Order | Appellate Authority | Time allowed for appeal |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 2 (zc) | Declaring inhabitant | District Magistrate | Fifteen days |
| 2. | 137 | Notice to fill up well, tank, etc., or to drain off or remove water. | Principal Director | Thirty days from service of notice. |
| 3. | 138 | Notice requiring the owner to provide latrine, urinal, cesspool dust-bin or other receptacle. | Board | Fifteen days from service of notice. |
| 4. | 139 | Notice requiring provision of sanitary facilities in market, school, theatre or other place of public resort. | Board | Fifteen days from service of notice. |
| 5. | 142 | Notice for removal of congested building. | General Officer Commanding-in-chief, the Command | Thirty days from service of notice. |
| 6. | 144 | Notice requiring a building to be repaired or altered so as to remove sanitary defects. | Principal Director | Thirty days from service of notice. |
| 7. | 147 | Notice prohibiting owner or occupier to use a building or part of a building for human habitation. | Principal Director | Twenty-one days from service of notice. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 8. | 183 | Order directing a person to remove from the Cantonment and prohibiting him from re-entering it without permission. | General Officer Commanding-in-Chief, the Command | Thirty days from service of notice. |
| 9. | 190 | Notice requiring maintenance or closing of private source of public drinking water supply. | Board | Fifteen days from service of notice. |
| 10. | 192 | Notice requiring the owner, lessee or occupier of a building or land to obtain water from a source of public water supply Board. | Board | Fifteen days from service of notice. |
| 11. | 195 | Notice for cutting off the connection between any source of public water-supply and any building or land to which water is supplied. | Board | Fifteen days from service of notice. |
| 12. | 238 | (a) Refusal to sanction the erection or re-erection of a building in a civil area. | Principal Director | Thirty days from service of communication. |
| | | (b) Refusal to sanction the erection or re-erection of a building in a Cantonment (other than a civil area). | General Officer Commanding-in-Chief, the Command | Thirty days from service of communication. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 13. | 239 | Order of stoppage of building or works in certain cases | Board | Thirty days from service of communication. |
| 14. | 248 | (a) Notice to stop erection or re-erection of, or to alter or demolish, a building in a civil area | Principal Director | Thirty days from service of communication. |
| | | (b) Notice to stop erection or re-erection of, or to alter or demolish, a building in a Cantonment (other than a civil area). | General Officer Commanding-in-Chief, the Command | Thirty days from service of communication. |
| 15. | 252 | Notice requiring the owner or the occupier to alter or remove any projection or encroachment | Board | Thirty days from service of notice. |
| 16. | 253 | Notice to pull down or otherwise deal with a building newly erected or re-built without permission over a sewer, drain, culvert, water-course or water-pipe. | Board | Thirty days from service of notice. |
| 17. | 273 | Notice prohibiting or restricting the use of a slaughter house | Board | Twenty-one days from service of notice. |
| 18. | 297 | Notice to remove, repair, protect, or enclose a building, wall or anything affixed thereto, or well, tank reservoir, pool, depression or excavation. | Board | Thirty days from service of notice. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 19. | 302 | Notice directing disorderly person to remove from cantonment and prohibiting him from re- entering it without permission. | District Magistrate | Thirty days from service of notice |

*The question was put and the motion was adopted.*

*Schedule V, as amended, was added to the Bill.*

CLAUSE-I

**Short Title, extent and Commencement**

MR. DEPUTY CHAIMAN: There is one amendment, (No. 3), by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 3) That at page 1, line 4, ***for*** the figure "2003" the figure "2006" be **substituted.**

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause I, as amended, was added to the Bill.*

ENACTING FORMULA

MR. DEPUTY CHAIMAN: There is one amendment, (No. 2), by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 2) That at page 1, line 1, ***for*** the word, "fifty-fourth", the word "Fifty Seventh" be ***substituted.***

*The question was put and the motion was adopted.*

*The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

LONG TITLE

MR. DEPUTY CHAIMAN: There is one amendment, (No. 1), in the Title by the Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

(No. 1) That at page 1, in the long title the words "proper regulation, control and management of defence lands including extension of cantonment laws to such lands situated throughout the territory of India" be *deleted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*The Title, as amended, was added to the Bill.*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

*That the Bill, as amended, be passed.*

*The question was put and the motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIMAN: Now, we shall take up the Food Safety and Standards Bill, 2006.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, अब इस बिल को कल ले लें ...(व्यवधान)... सर, अब बहुत समय हो गया है, इसे कल ले लेते हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have decided to sit up to 8 o'clock.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। वैसे भी हमने कैन्टोनमेंट बिल के लिए चार घंटे रखे थे, इसलिए अब आप इसे रहने दीजिए, इसे हम कल ले लेते हैं। सर, सुबह से भूखे बैठे हुए हैं ..(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Parliamentary Affairs Minister has told... *(Interruptions).*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, फूड मिनिस्टर खाने-पीने का भी कुछ प्रावधान करवा दें ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: हां, फूड मिनिस्टर यह करेंगे ...(व्यवधान)...

SHRI PENUMALLI MADHU (Andhra Pradesh): Sir, nobody is in the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You see, we have not conducted any legislative business.